बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 182

एआई संचालित अर्थव्यवस्था

नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक के इस्तेमाल के जरिये एक त्वरित आर्थिक विकास का ढांचा पेश किया गया है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सिर्फ उत्पादकता में सुधार से वर्ष 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद में अतिरिक्त 500-600 अरब डॉलर इजाफा हो सकता है और अनुसंधान एवं विकास में नवाचार को तेज करने से अतिरिक्त 280-475 अरब डॉलर रकम जुड़ सकती है। भारत में तकनीक की जानकारी रखने वाला एक विशाल कार्यबल है और यहां डिजिटल ढांचे का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। इनके अलावा, आरऐंडडी तंत्र का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। इन खूबियों की बदौलत भारत वैश्विक एआई वैल्यू पूल में 10-15 फीसदी हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। मगर केवल अवसर मौजूद रहना ही काफी नहीं है। सरकार, उद्योग और शिक्षा-व्यवस्था के बीच मजबूत समन्वय एक ठोस एवं समावेशी एआई तंत्र विकसित करने के लिए आवश्यक है।

इसी दिशा में सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये से भी अधिक लागत से 'इंडिया एआई मिशन' शुरू किया है। इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य डेटा लैब एवं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) स्थापित करना, भारत के लिए विशिष्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करना और राष्ट्रीय कौशल योजना में एआई का समावेश करना है। यह पहल संप्रभु डेटा ढांचा और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए बड़े स्तर पर एआई अपनाने की खूबियां तैयार करेगी। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में जिन संभावनाओं का जिक्र किया गया है उनमें वैश्विक डेटा केंद्र बनने की भारत की क्षमता भी शामिल है। डेटा अगले चरण के एआई मॉडलों को ताकत दे सकते हैं और विनिर्माण, दवा, वित्तीय सेवाएं और वाहन उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेज विकास के द्वार खोल सकते हैं।

विशेषकर, दवा क्षेत्र बड़े बदलाव लाने वाली संभावनाओं से भरा है। वर्तमान में भारत के दवा बाजार का 80 फीसदी हिस्सा जेनरिक दवाओं तक सीमित है क्योंकि आरऐंडडी पर अधिक खर्च आता है और इसमें समय भी काफी लगता है। मगर एआई के माध्यम से दवाओं की खोज पर आने वाली लागत और इनके विकास में लगने वाला समय दोनों कम किए जा सकते हैं जिससे भारत जेनरिक दवाओं के निर्माता से वैश्विक नवाचारकर्ता बन सकता है। विशाल जीन पूल और औषध विज्ञान में विशेषज्ञता जैसी खूबियों की बदौलत भारत स्वयं को नए नवाचारी दवा विकास के केंद्र के रूप में तैयार कर सकता है। इसी तरह, सॉफ्टवेयर की मदद से संचालित वाहनों (एसएवी) के साथ वाहन क्षेत्र नए बदलाव के लिए तैयार दिख रहा है। सॉफ्टवेयर की मदद से संचालित वाहनों में एआई डिजाइन, परीक्षण और उपकरणों के संयोजन को संचालित कर सकता है। एआई-रेडी औद्योगिक पार्क की स्थापना, स्वच्छ ऊर्जा कारखानों के विकास और दमदार प्रदर्शन करने वाले लैब एवं कौशल केंद्रों की बदौलत भारत त्वरित नवाचार को बढ़ावा दे सकता है और भविष्य में अगली पीढ़ी के यातायात साधनों का पुरोधा बन सकता है। हालांकि, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नीति आयोग की इस रिपोर्ट की प्रस्तुति के अवसर पर कहा कि दो चुनौतियां भी सामने हैं। इनमें तकनीक के इस्तेमाल में तेजी लाने के साथ ही नवाचार की प्रगति बाधित किए बिना नियामकीय ढांचा तैयार करना शामिल है ताकि नागरिकों के हित सुरक्षित रहें। डेटा सुरक्षा एवं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा (डीपीडीपी) अधिनियम में प्रस्तावित विस्तृत नियम आने के बाद डेटा गोपनीयता पर स्थिति साफ हो जाएगी। इससे एआई ढांचे से जुड़ी एक सबसे बड़ी चिंता खत्म हो सकती है। इस रिपोर्ट में मानव पूंजी से जुड़ी अहम चुनौती भी रेखांकित की गई है।

यह सच है कि एआई तकनीक कई बड़े हुनर वाली भूमिकाओं को अंजाम दे सकती है मगर यह कई नौकरियां (खासकर नियमित एवं कम कौशल वाले खंडों में) भी समाप्त कर सकती है। कार्य बल को बदलते समय के साथ आवश्यक हुनर से लैस करने, विस्थापित कामगारों को हुनरमंद बनाने (खासकर छोटे कारोबारों एवं पिछड़े क्षेत्रों में) और एआई क्षमताओं तक सबकी पहुंच सरल बनाने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है। भारत को पूरी जवाबदेही के साथ एआई के इस्तेमाल के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। संप्रभु ढांचे में निवेश, क्षेत्र विशेष डेटा प्लेटफॉर्म जैसे विनिर्माण डेटा ग्रिड का विकास, अनुकूलित एआई-कौशल तंत्र तैयार करने और समान पहुंच सुनिश्चित कर भारत न केवल आर्थिक वृद्धि तेज कर सकता है बल्कि एक टिकाऊ कारोबारी तंत्र भी तैयार कर सकता है।

अजय मोहंती

मजबूत वित्तीय तंत्र के लिए चाहिए अल्पावधि विकल्प

साप्ताहिक विकल्प सौदों पर प्रतिबंध लगाना बाजार विकास के नजरिये से उचित नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए ये आवश्यक हैं। बता रहे हैं अजय शाह और उर्वीश बीडकर

देश में यह बहस चल रही है कि क्या सरकार को साप्ताहिक विकल्प अनुबंधों (वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट) पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। यह बहस उन नियामकीय चिंताओं के बाद उत्पन्न हुई है जो खुदरा भागीदारी बढ़ने और बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत ट्रेडर्स को होने वाले नुकसान से उत्पन्न हुई हैं। इन चिंताओं को समझा जा सकता है लेकिन प्रतिबंध लगाना एक नीतिगत चूक होगी। यह समस्या का गलत निदान है और इससे कड़ी मेहनत से हासिल किए गए वित्तीय बाजार के विकास को नुकसान पहुंचने का जोखिम है। हमें क्रियाशील बाजारों को नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें वैश्विक अनुभवों से सीख लेनी चाहिए और एक अधिक मजबूत वित्तीय माहौल तैयार करने की दिशा में बढ़ना चाहिए।

इस बहस को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है मानो यह सटोरिया गतिविधि और निवेशक संरक्षण के बीच कोई समझौता जैसा हो। वित्तीय अर्थशास्त्र के नजरिये से देखें तो मामला यह है कि क्या भारत को अधिक नकदीकृत और अधिक संपूर्ण बाजार तैयार करने की दिशा में बढ़ना जारी रखना चाहिए। वित्तीय डेरिवेटिव्स केवल सट्टेबाजी के साधन नहीं हैं; वे जोखिम को अनुकूलित करने के लिए मौलिक साधन भी हैं।

नोबेल पुरस्कार विजेता केनेथ एरो और गेरार्ड डेब्रू का सैद्धांतिक आदर्श कहता है, 'एक संपूर्ण बाजार वह है जहां हर संभावित हालात के लिए एक सुरक्षा मौजूद हो ताकि किसी भी जोखिम से पूरी तरह बचाव संभव हो सके।' यह अलग बात है कि ऐसे पूर्ण बाजार की वास्तव में प्राप्त करना असंभव है किंतु वित्तीय नवाचार लगातार उस दिशा में बढ़ने की कोशिश करता है। लघु-अवधि के विकल्प हमारे पास उपलब्ध सबसे व्यावहारिक उपाय हैं जो एकदिन वाली एरो प्रतिभूतियों के समान हैं। ये प्रतिभागियों को एक ही दिन किसी घटना के जोखिम से अलग रखने और उसी दिन कारोबार करने की भी सुविधा देते हैं। ये पूरे प्रतिभूति बाजार की तरलता और दक्षता बढ़ाने जैसा आर्थिक कार्य भी करते हैं। इन साधनों पर प्रतिबंध हमारे बाजारों को कम कुशल और कम नकदीकृत बनाएगा।

भारतीय इक्विटी डेरिवेटिव्स व्यवस्था ने प्रगति की है लेकिन ज्यादा ध्यान कुछ लोगों को नुकसान से बचाने पर केंद्रित हो गया है। खुदरा नुकसान के आंकड़े चिंतित करने वाले हैं लेकिन इसका प्रस्तावित हल भी खामियों से भरा है। दिक्कत साधन में नहीं है। हाल में जेन स्ट्रीट मामले के बाद निगरानी अधिक मजबूत हो गई जब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रमुख ने उचित ही 'निगरानी' को एक मुद्दा बताया। उत्पाद को प्रतिबंधित करना तो पूरे बाजार को दंडित करने के समान है जबकि नाकामी की वजह निगरानी या व्यक्तिगत निर्णय है। एक जीवंत उदाहरण हमें इस बारे में जानकारी प्रदान करता है।

मई 2022 में शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज यानी सीबीओई ने एसऐंडपी500 सूचकांक पर विकल्प की पेशकश की जिसकी एक्सपायरी दैनिक थी। इसे ओडीटीई ऑप्शंस नाम दिया गया था। साल 2023 के मध्य तक ओडीटीई की ट्रेडिंग एसऐंडपी500 के कुल विकल्प कारोबार में 43 फीसदी हिस्सेदार हो गई। इसका नोशनल डेली वॉल्यूम करीब एक लाख करोड़ डॉलर का था। यह जबरदस्त वृद्धि दिखाती है कि ये उत्पाद मूल्यवान हैं और वे स्वैच्छिक उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी काम कर रहे हैं। आशंकाओं के विपरीत इस जबरदस्त वृद्धि के चलते व्यवस्थागत अस्थिरता नहीं हुई। इससे एक गहन, नकदीकृत और संतुलित माहौल तैयार हुआ। सीबीओई के आंकड़े बताते हैं कि बाजार केवल एकतरफा सट्टेबाजी का उन्माद नहीं है। खुदरा ग्राहक लगभग 55 फीसदी हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि परिष्कृत संस्थागत ग्राहक शेष 45 फीसदी का योगदान करते हैं।

भारतीय विमर्श में अल्पावधि के विकल्प को अक्सर केवल सट्टेबाजी वाले साधन कहकर खारिज कर दिया जाता है। लेकिन शोधकर्ताओं ने सीबीओई के आंकड़ों का अध्ययन करके यह पाया है कि इनका उपयोग संस्थानों द्वारा घटनाओं की सटीक हेजिंग से लेकर रणनीतिक इंट्राडे कारोबार जैसे परिष्कृत और विवेकपूर्ण तरीकों से किया जाता है। आशंका जताई जाती है कि ऐसे उत्पाद बाजार को अस्थिर करते हैं लेकिन तथ्य इसकी पुष्टि नहीं करते। अमेरिका का अनुभव इस बात का प्रमाण है कि एक परिपक्व वित्तीय तंत्र अल्पावधि के विकल्प कारोबार में गहराई पा सकता है। ऐसी गहराई जो विभिन्न प्रकार के बाजार प्रतिभागियों द्वारा चुने गए उपयोगी अनुप्रयोगों को संभव बनाती है। भारत को उच्च गुणवत्ता वाले शोध की आवश्यकता है जो भारतीय हालात में घटित हो रही गतिविधियों की प्रकृति को समझ सके ताकि नीति निर्माण को केवल धारणाओं, पूर्वाग्रहों और राजनीतिक अर्थशास्त्र से बचाया जा सके।

प्रतिबंध लगाने का तर्क संरक्षणवाद पर आधारित है, जो आर्थिक स्वतंत्रता के एक मूल सिद्धांत का विरोध करता है। यानी सहमति रखने वाले वयस्कों को अनुबंध करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य की भूमिका अनुबंधों को लागू करने और धोखाधड़ी को रोकने की है, जोखिम लेने पर रोक लगाने की नहीं।

कई महत्त्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां, जैसे एंजेल निवेश या उद्यमिता में विफलता की दर बहुत अधिक होती है, फिर भी सरकार व्यक्ति के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करती। अधिकांश नए व्यवसाय विफल हो जाते हैं। लेकिन सरकार यह नहीं कहती कि किसी व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करने से पहले कोई परीक्षा देनी चाहिए।

देश की नीतिगत बहसें अक्सर 'अच्छी हेजिंग' और 'बुरी सटोरिया गतिविधियों' के बीच बंट जाती है। हकीकत यह है कि सटोरिये नकदीकरण के लिए जीवनरेखा की तरह होते हैं। केवल सट्टेबाजी को रोकने के उद्देश्य से किसी उत्पाद पर रोक लगाना अनिवार्य रूप से वैध हेजिंग करने वालों को नुकसान पहुंचाता है। इससे बाजार में नकदी की कमी होती है। जब डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग पर रोक लगाई जाती है तो बुनियादी जोखिम खत्म नहीं होता। कुछ हद तक गतिविधियों के धीमा होने से नकदीकरण को नुकसान पहुंचता है। इससे जोखिम हस्तांतरण की मांग कम पारदर्शी माध्यमों की ओर चली जाती है और प्रतिभागी भारतीय कानून के दायरे से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में नियामकों के लिए यह आकलन करना मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में जोखिम निर्माण कितना हो रहा है। प्रतिभूति बाजारों का लक्ष्य है नकदीकृत और सक्षम बाजार तैयार करना। यह वित्तीय विकास भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए अहम है। यह हमारी नीतियों के केंद्र में होना चाहिए। हमारे पास प्रतिबंध से बेहतर उपाय मौजूद हैं। इसका हल कम खुदरा भागीदार नहीं बल्कि अधिक संस्थागत प्रतिभागी हैं। ऐसी नीति होनी चाहिए जो घरेलू संस्थानों को डेरिवेटिव्स कारोबार के लिए सक्षम बनाए। नियामक को जोखिम खुलासे और वित्तीय साक्षरता पहलों के जरिये पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए।

भारतीय इक्विटी बाजार का महत्त्व केवल निजी निवेश गतिविधियों को आकार देने में इक्विटी वित्तपोषण के प्रभुत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जिंस, मुद्राओं और सरकारी बॉन्ड्स में भविष्य की प्रगति के लिए एक संस्थागत आधार भी प्रदान करता है। इस संभावित विकास को साकार करने के लिए इक्विटी बाजार में कामयाबी जरूरी है। अल्पावधि के विकल्प डेरिवेटिव्स बाजार का एक स्वस्थ और सफल पहलू हैं। नीति-निर्माताओं को इन्हें किसी खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए ताकि एक अधिक परिष्कृत और लचीली वित्तीय प्रणाली निर्मित की जा सके।

(लेखक क्रमशः एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता और न्यूयॉर्क के एस्पायर मैकरो में प्रिंसिपल हैं)

देश में अव्वल मगर दुनिया के आगे फिसड्डी

अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए शुल्क विश्व व्यापार संगठन के वैश्विक व्यापार सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं। मगर इन शुल्कों के बाद भारत में यह बहस भी छिड़ गई है कि देश वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के लिए क्या कदम उठा सकता है।

औद्योगिक संगठनों, कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों और वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों ने भूमि अधिग्रहण, बिजली क्षेत्र, कर, अनुपालन संबंधित प्रक्रियाओं और श्रम कानूनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अगले चरण के सुधार करने का अनुरोध किया है। ये सुधार कारोबार संचालन आसान बनाने के साथ ही भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्द्धा में टिके रहने की चुनौती क्षमता भी बढ़ाएंगे।

इस बीच, नीति-निर्माताओं के कुछ अपने विचार हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का 1.4 अरब लोगों का मजबूत घरेलू बाजार एक सहज एवं आरामदेह क्षेत्र बन गया है और भारतीय उद्योग जगत को मोटा मुनाफा भी दे रहा है इसलिए उन्हें दुनिया में अवसरों की तलाश में निकलने की जरूरत महसूस नहीं होती है। गोयल की टिप्पणी केवल उनकी नाराजगी या तंज बता कर खारिज नहीं की जा सकती। काफी हद तक यह सच है कि बड़े भारतीय विनिर्माण आधारित औद्योगिक घराने निर्यात बढ़ाने के जोरदार प्रयास करने के बजाय कई तरह के उद्योगों में उतरने और घरेलू बाजार में विस्तार में अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं। कई भारतीय ब्रांड की दुनिया में अच्छी खासी पहचान है मगर वे दुनिया की नामी कंपनियों की फेहरिस्त में शुमार नहीं हैं। कुछ मायनों में इसका संबंध 1991 के आर्थिक सुधारों से पूर्व की व्यावसायिक नीतियों से है। तब सरकार सभी व्यावहारिक उद्देश्यों से यह तय करती थी कि कोई कंपनी कितना उत्पादन कर सकती है। प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान सरकार यह भी तय करती थी कि कोई कंपनी किस क्षेत्र में कारोबार करने के लिए उतर सकती है, उसमें कितनी इकाइयां हो सकती हैं। सरकार यह भी तय करने से पीछे नहीं हटती थी कि कंपनियां किस कीमत पर बाजार में अपने उत्पाद बेच सकती हैं।

प्रसेनजित दत्ता

हालांकि, ऐसे दौर भी आए जब सरकार की तरफ से अधिक हस्तक्षेप नहीं हो रहे थे मगर भारतीय औद्योगिक घरानों को तब तक लाइसेंस का प्रबंधन करने की आदत लग चुकी थी। वे जो भी उत्पादन करते थे वे उपभोक्ताओं के पास अधिक विकल्प नहीं होने के कारण हाथोंहाथ बिक जाते थे। यह बात कुछ हद तक स्पष्ट करती है कि हमारे पास एक या दो क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली विशाल कंपनियों के बजाय इतने सारे भारतीय कंपनी समूह क्यों हैं। जनरल मोटर्स या फोर्ड ने कार एवं इनसे संबंधित उपकरण बनाकर अपनी एक खास पहचान बनाई। उन्होंने शायद ही कभी किसी दूसरे अलग क्षेत्रों में प्रवेश करने की कोशिश की। निश्चित रूप से वे शुरू में अमेरिका में बड़े औद्योगिक समूह माने जाते थे मगर वे ज्यादातर क्षेत्रों में अधिक देर तक नहीं टिक पाए।

दूसरी ओर भारत में बड़े समूहों का उदय हुआ जिनमें टाटा, बिड़ला, गोदरेज, महिंद्रा एवं अन्य शामिल थे। जो समूह शुरू में अपना कारोबार एवं आकार बढ़ाने के लिए एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, मगर उन्हें भी दूसरे भिन्न क्षेत्रों में विस्तार करने में सहजता महसूस हुई। ऐसा लगता है कि अभी भी स्थिति उनके लिए ऐसी ही है। यह बात रिलायंस और अदाणी समूह की विस्तार योजनाओं में आराम से दिख जाती है। हालांकि, अदाणी समूह कम से कम बंदरगाह क्षेत्र में एक बड़ी वैश्विक कंपनी बनने की जरूर कोशिश कर रहा है।

वर्ष 1991 के बाद स्थितियां बेहतर जरूर हुई मगर कई मुश्किलें बनी रहीं। सख्त नियमों और कम लागत पर पूंजी तक पहुंच आसान नहीं होने से केवल कुछ चुनिंदा उद्योग ही आगे बढ़ पाए क्योंकि वे तत्कालीन परिस्थितियों में आगे बढ़ना जानते थे जबकि कई अन्य उद्यम प्रतिस्पर्द्धा में टिक नहीं पाने के कारण छोटे और गैर प्रतिस्पर्धी बने रहे। कुछ क्षेत्रों ने तमाम मुश्किलों से मुकाबला कर आगे बढ़ने में सफलता हासिल की। वाहन सहायक उपकरण और जेनेरिक फार्मा इसके उदाहरण हैं लेकिन इनमें भी वैश्विक स्तर पर दमखम रखने वाली कंपनियां उंगर कर नहीं आईं हैं। पूर्व में और अब भी कुछ सम्मानजनक प्रयास हुए हैं। उदाहरण के लिए रॉयल एनफील्ड क्लासिक मोटरसाइकलों में एक वैश्विक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ दोष बढ़े भारतीय उद्योग समूहों पर लगाए जा सकते हैं जिन्होंने अपने आकार और संसाधनों के बावजूद वैश्विक स्तर पर धाक जमाने का लक्ष्य साधने के बजाय घरेलू प्रणाली का प्रबंधन करना पसंद किया। मगर सरकार को भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि उसकी नीतियां कहां गलत साबित हो गईं।

श्रम, अनुपालन, भूमि अधिग्रहण और अन्य समस्याओं पर काफी कुछ लिखा जाता है। ये सभी वास्तविक हैं मगर अक्सर जिस बात को दबा दिया जाता है वह यह है कि किसी भी सरकार ने घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्द्धा और गुणवत्ता बढ़ाने या उपभोक्ताओं के लिए लागत कम करने का कोई प्रयास नहीं किया। जिन ढांचे को फिर से बनाने के लिए फौरन कदम उठाने चाहिए। सरकार को सड़क मार्ग को तत्काल दुरुस्त करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों को माल नहीं भेज पाने के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है तथा सेब सड़ने लगे हैं।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

उपभोक्ता और उद्योग के बीच संतुलन का प्रयास

जीएसटी की नई दरों से कर ढांचे में संतुलन लाने का प्रयास दिखता है। कुछ वस्तुओं पर दरें घटने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वहीं विलासिता की वस्तुओं पर बढ़ोतरी से राजस्व संग्रह में मदद मिलेगी। छोटे कारोबारियों को भी सरल अनुपालन का लाभ मिलेगा। हालांकि दरों में बार-बार बदलाव उद्योग जगत में अनिश्चितता पैदा करता है। आवश्यक है कि दरें स्थिर और पारदर्शी रहें ताकि उपभोक्ता और व्यापारी दोनों को भरोसा मिल सके।

अमृतलाल मारू, इंदौर

देश में जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है उनमें से कई वस्तुओं का निर्यात भी होता है। इनमें से कुछ वस्तुओं का निर्यात उन देशों को होता है जहां उनका उत्पादन भारत की तुलना में कम लागत पर होता है। इसका एक उदाहरण है कपड़ा। भारत में कपड़ा उत्पादन की लागत बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया की तुलना में अधिक है। इसलिए भारत में बने कपड़ों की मांग इन देशों में कम है। इसी तरह, भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग चीन में कम है क्योंकि वहां इनका उत्पादन भारत की तुलना में कम लागत पर होता है। इसी तरह, भारत में बने रसायनों की मांग अमेरिका में कम है क्योंकि वहां इनका उत्पादन भारत की तुलना में कम लागत पर होता है।

इसके विपरीत, भारत में बने सॉफ्टवेयर की मांग अमेरिका में अधिक है क्योंकि वहां इनका उत्पादन भारत की तुलना में अधिक लागत पर होता है। इसी तरह, भारत में बने दवाओं की मांग अमेरिका में अधिक है क्योंकि वहां इनका उत्पादन भारत की तुलना में अधिक लागत पर होता है।

इस प्रकार, भारत में बने उत्पादों की मांग उन देशों में अधिक है जहां उनका उत्पादन भारत की तुलना में अधिक लागत पर होता है। इसका कारण यह है कि भारत में श्रम, भूमि और पूंजी की लागत अन्य देशों की तुलना में कम है। इसलिए भारत में बने उत्पादों की मांग उन देशों में अधिक है जहां उनका उत्पादन भारत की तुलना में अधिक लागत पर होता है।

इसके विपरीत, भारत में बने उत्पादों की मांग उन देशों में कम है जहां उनका उत्पादन भारत की तुलना में कम लागत पर होता है। इसका कारण यह है कि भारत में श्रम, भूमि और पूंजी की लागत अन्य देशों की तुलना में अधिक है। इसलिए भारत में बने उत्पादों की मांग उन देशों में कम है जहां उनका उत्पादन भारत की तुलना में कम लागत पर होता है।

इस प्रकार, भारत में बने उत्पादों की मांग उन देशों में अधिक है जहां उनका उत्पादन भारत की तुलना में अधिक

चिंतन

भारतवर्ष को एक बार फिर स्वदेशी आंदोलन की जरूरत

अठारह सौ सत्तावन का विद्रोह हो, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन, भारत की आजादी की लड़ाई में सारे वो पल थे, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इन आंदोलनों ने न केवल आजादी की लड़ाई को तेज धार दी, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। आजादी की इस लड़ाई में स्वदेशी आंदोलन का अहम योगदान रहा। महात्मा गांधी ने 22 अगस्त 1921 को विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी' का नारा बुलंद किया। यह घटना न केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था, बल्कि भारतीयों में आत्मसम्मान और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम जगाने का एक शक्तिशाली कदम भी था। इस ऐतिहासिक क्षण ने स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी भावना को प्रज्ज्वलित करने का काम किया। गांधीजी का मानना था कि स्वदेशी की भावना का पालन करने वाले व्यक्ति को केवल अपने निकटवर्ती पड़ोसियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए और उन उद्योगों को कुशल बनाकर उनकी सेवा करनी चाहिए, और उन क्षेत्रों में उन्हें मजबूत करना चाहिए जहां उनकी कमी है। इससे न केवल गरीबी से मुक्ति मिलेगी बल्कि सहकारिता का भाव भी जागृत होगा। आज देश को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। स्वदेशी केवल वस्तु नहीं, अपितु एक विचार है। आजादी से पहले विदेशी दासता के विरुद्ध संघर्ष का माध्यम बना था और अब इसे देश के विकास की धुरी बनने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर बुधवार को मध्यप्रदेश के धार में अमेरिका के ट्रम्प टैरिफ का जवाब देते हुए स्वदेशी चीजें खरीदने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि आप जो भी खरीदें, वो देश में ही बना होना चाहिए। उसमें पसीना किसी देशवासी का होना चाहिए। आप जो भी बेचें, वह देश में ही बना होना चाहिए। हर दुकान पर बोर्ड हो- गर्व से कहें, ये स्वदेशी है। हमारे विदेशी प्रेम के चलते न केवल अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है बल्कि हम अनेक चीजों के लिए विदेशी ताकतों के अधीन होकर रह गए हैं। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने का सबसे आसान और कारगर तरीका यही है कि रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुओं में हम अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का स्वयं उपयोग करें और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करें। प्रशासन, मीडिया आदि के द्वारा भी स्वदेशी वस्तुओं का अधिक-से-अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए और स्वदेशी के महत्व को जन-जन तक पहुंचाया जाए। अब आप जरा ध्यान से समझें कि भारत एक घर है, और अमेरिका या यूरोप दूसरा घर। यदि आप भारत वासी होकर अमेरिका के घर की दुकान से सामान खरीदोगे तो वो पैसा और उसके अंदर की कमाई अमेरिका के घर के सुधार में ही लगेगी, वो पैसा तो गया भारत से। हम अगर अपने स्वदेश की चीजों पर पैसा खर्चेंगे तो जो हमारे उत्पादक भाई बंधू हैं उन्हें और पैसा मिलेगा, इससे वो और अच्छी वस्तुओं का निर्माण करने में लगायेंगे। कुछ त्याग आप और हम करेंगे तो ही ये देश खड़ा होगा, तेज गति से विकास करेगा। विज्ञापनों पर मत जाइये अपनी अक्ल लगाइए। कोई भी वस्तु खरीदें तो याद रखें कि वो देश का भला करने के लिए है या नहीं। स्वदेशी अपनाकर हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत तो करते ही हैं। स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं। यह अपनी संस्कृति और पारंपरिक कलाओं का संरक्षण भी करता है, इसीलिए जरूरी है कि स्वदेशी को आंदोलन का रूप दें।

आर्थिकी
डॉ. जयंतीलाल भंडारी

ट्रंप की टैरिफ चुनौतियों के बीच देश में 22 सितंबर से लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई घटी हुई दरों से उपभोक्ता मांग में भारी वृद्धि होगी और इससे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले एमएसएमई मजबूत होंगे। वस्तुतः अभी जीएसटी सुधार के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक भारत को दुनिया का विकसित देश बनाने के लिए एमएसएमई की विभिन्न चुनौतियों के समाधान के मद्देनजर नई रणनीति पर भी आगे बढ़ना जरूरी है। उम्मीद करें कि सरकार अभी भी मौजूद जीएसटी संबंधित कुछ उलझनों के समाधान से देश में एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाएगी।

जीएसटी सुधार से मजबूत होंगे एमएसएमई

यकीन ट्रंप की टैरिफ चुनौतियों के बीच देश में 22 सितंबर से लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई घटी हुई दरों से उपभोक्ता मांग में भारी वृद्धि होगी और इससे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले एमएसएमई मजबूत होंगे। वस्तुतः अभी जीएसटी सुधार के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक भारत को दुनिया का विकसित देश बनाने के लिए एमएसएमई की विभिन्न चुनौतियों के समाधान के मद्देनजर नई रणनीति पर भी आगे बढ़ना जरूरी है। एमएसएमई से जुड़े जीएसटी सुधार प्रमुख रूप से ऑटोमोबाइल, ड्राक्फ्रूट्स उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी उत्पाद, पेपरमिल, लॉजिस्टिक्स, हस्तशिल्प, आवास निर्माण उत्पाद क्षेत्रों की इकाइयों को भारी लाभ देंगे। एमएसएमई क्षेत्र में जीएसटी दरों को कम किए जाने की रणनीति आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करने और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने तथा विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीण उद्यमियों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए रोजगार को बढ़ावा देगी।

इससे खासतौर से वस्त्र, खिलौने, हस्तशिल्प, चमड़ा और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह बात महत्वपूर्ण है कि दोपहिया वाहनों, कारों, बसों और ट्रैक्टरों पर कम जीएसटी से मांग बढ़ेगी, जिससे टायर, बैटरी, ग्लास, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के एमएसएमई को लाभ होगा। ट्रैक्टरों पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी (1800 सीसी) करने से भारत की वैश्विक स्तर पर ट्रैक्टर विनिर्माण में अग्रणी बनने की स्थिति मजबूत होगी। साथ ही इससे संबद्ध एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा। वाणिज्यिक माल वाहनों (ट्रक, डिलीवरी वैन) पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिए जाने से माल ढुलाई, लॉजिस्टिक्स लागत, महंगाई का दबाव कम होने से एमएसएमई को लाभ होगा। ऐसे में निश्चित रूप से जीएसटी की नई स्लैब से आम आदमी, छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को राहत मिलेगी। चाहे आम आदमी के इस्तेमाल की चीज हों, चाहे वह किसानों से जुड़ी वस्तुएं हों, चाहे वह मध्यम वर्ग से संबंधित वस्तुएं हों, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में एमएसएमई को दी गई बड़ी जीएसटी राहत अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देगी। यद्यपि अब जीएसटी दर घटने से एमएसएमई को कर राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इसके अलावा एमएसएमई के समक्ष डिजिटल ढांचा, कुशल श्रमिक, बाजार पहुंच, फंडिंग की कमी टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, डेटा सुरक्षा और स्किल डेवलपमेंट की चुनौतियां खड़ी हुई हैं। आईटी सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स के समक्ष व्यावहारिक मार्गदर्शन, एक्सेस और प्रारंभिक निवेश की चुनौती है। खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योगों में खराब तकनीक और कमजोर लॉजिस्टिक व्यवस्था के कारण गुणवत्ता में कमी की चुनौती है। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति और बड़ी कंपनियों से भुगतान में देरी एमएसएमई के विकास में बड़ी बाधा हैं। सिडबी की रिपोर्ट के मुताबिक अभी एमएसएमई के लिए सरल कर्ज की प्राप्ति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि एमएसएमई क्षेत्र देश में उत्पादन, निर्यात और रोजगार में लगातार अपनी अहम भूमिका बढ़ाता जा रहा है। विगत 21 जुलाई को राज्यसभा में एमएसएमई मंत्री ने बताया कि देश में इस समय पंजीकृत 6.5 करोड़ एमएसएमई

करीब 28 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई का योगदान करीब 30.1 फीसदी है। देश के एमएसएमई विनिर्माण में 35.4 फीसदी और निर्यात में 45.73 फीसदी योगदान दे रहे हैं। निश्चित रूप से अब इस समय तेज विकास की रणनीति के तहत तेजी से आकर ले रहे भारत के एफटीए में जिस तरह एमएसएमई के हितों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, उससे देश के एमएसएमई के लिए नई वैश्विक संभावनाएं भी उभर कर दिखाई दे रही हैं। निसंदेह एमएसएमई के समक्ष ऊंचे टैरिफ से निर्मित चिंताओं को दूर करने हेतु मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में में एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के उद्देश्य से बहुआयामी उपायों की जो एक वृहद शृंखला प्रस्तुत की गई है, उसके क्रियान्वयन पर तेजी से आगे बढ़ना होगा। इसके तहत वित्तीय सहायता और खरीद नीतियों से लेकर क्षमता निर्माण और बाजार एकीकरण तक की पहल शामिल हैं। प्रमुख पहलों में उद्यम पंजीकरण पोर्टल, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएमईजीपी, स्फूर्ति और एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति शामिल हैं, जिनका उद्देश्य उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, रोजगार बढ़ाना और अनौपचारिक क्षेत्रों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना है। उद्योगों का विस्तार करने और दक्षता में सुधार करने में मदद करने के लिए, एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा बढ़ा दी गई है। चालू वित्त वर्ष 2025- 26 में एमएसएमई को दिए जाने वाले कर्ज का लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में करीब 20 फीसदी बढ़ाकर सुनिश्चित किया गया है। सरकार नियंतकों को सहारा देने के लिए 2250 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन को तेजी से लागू करने और बिना रेहन के कर्ज दिए जाने की डगर पर आगे बढ़ रही है। टैरिफ तूफान के बीच एमएसएमई की क्षमताओं को उन्नत करने, संचालन को सुव्यवस्थित करने तथा निर्यात झटके से निपटने के लिए एमएसएमई को नीतिगत समर्थन का लाभ दिया जाना होगा। अब एमएसएमई के बढ़ावा देने की नई योजना, कारोबार में सरलता, वैश्विक बाजार में सरल पहुंच, अनुपालन बोझ में कमी, जीएसटी दरों में सरलता पर ध्यान देना। एमएसएमई को सीधे मदद और प्रक्रियाओं के माध्यम से मदद, दोनों ही डगर पर आगे बढ़ना होगा। इससे उनके व्यापक ढांचे में लचीलापन मिल सकेगा और उनके अनुपालन लागत में भी कमी आएगी। सरकार के द्वारा एमएसएमई के कारोबार करने को आसान बनाने और घरेलू खपत को बढ़ाने के तरीकों पर नए सिरे से आगे बढ़ना होगा। नई सप्लाई चेन और नए बाजारों की तलाश की जाने होगी। विदेशों में वेयरहाउसिंग की सुविधा और वैश्विक ब्रांडिंग पहल से भी निर्यात का बाजार बढ़ाना होगा। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना होगा कि बुनियादी ढांचे की मजबूती, अधिक लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाने, ब्याज समतुल्य योजना को फिर से शुरू किया जाने तथा ऋण गारंटी कार्यक्रमों का विस्तार करने जैसे उपायों से एमएसएमई को वित्तीय राहत और स्थिरता प्रदान की जानी होगी। एमएसएमई के हित में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं का विस्तार किए जाने से विशेष रूप से निर्यात-उन्मुख एमएसएमई लाभांवित होंगे। नवाचार की नई लहर एमएसएमई के लिए नया अध्याय लिख सकती है। उम्मीद करें कि सरकार अभी भी मौजूद जीएसटी संबंधित कुछ उलझनों कारोबार सरलता, डिजिटल ढांचा, कुशल श्रमिक, वैश्विक बाजार पहुंच, फंडिंग की कमी, नई टेक्नोलॉजी के सहयोग, स्किल डेवलपमेंट अनुपालन बोझ में कमी जैसी अहम चुनौतियों के समाधान से देश में एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाएगी और इससे देश आगे बढ़ेगा।

(लेखक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है। ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

अभियान
विवेक शुक्ला

दो सफल ऑपरेशन के बाद अंतिम सांसें गिनते आतंकी

बीते कुछ महीनों में, विशेष रूप से 2025 में, दो प्रमुख अभियान ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने देश-विरोधी ताकतों को गहरी चोट पहुंचाई है। ये अभियान आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे कुछ रोगों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के उदाहरण हैं। इन ऑपरेशनों के सफल परिणामों ने न केवल सीमापार आतंकवादियों और आंतरिक विद्रोहियों को धूल चटा दी है, बल्कि पूरे राष्ट्र को एकजुटता और आत्मविश्वास का संदेश भी दिया है। ऑपरेशन महादेव जम्मू-कश्मीर की धरती पर एक मील का पत्थर साबित हुआ, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का जीवंत प्रमाण है। जुलाई 2025 में शुरू हुआ यह अभियान, विशेष रूप से पहलगाम हमले के मास्टरमाइंडस को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। पहलगाम हमला, जिसमें निर्दोष पर्यटकों और नागरिकों को निशाना बनाया गया था, ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के संयुक्त प्रयासों ने मात्र 14 दिनों में तीन शीर्ष पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन ने देश-विरोधी ताकतों को धूल में मिला दिया क्योंकि यह केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक झटका था। लश्कर जैसे संगठन, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के प्रतीक हैं, अब भारत की सीमाओं के पास सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। पहले जहां ये तत्व घुसपैठ कर निर्दोषों का खून बहाते थे, अब वे छिपने के लिए मजबूर हैं। उधर, ऑपरेशन महादेव ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां किसी भी साजिश को कुचलने में सक्षम हैं। नतीजतन, जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है, और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में विश्वास बहाल हुआ है। यह सफलता न केवल स्थानीय आबादी को सुरक्षा का आश्वासन देती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की मजबूत इच्छाशक्ति को प्रदर्शित करती है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे 'सिंदूर स्ट्राइक' का हिस्सा बताते हुए कहा कि यह आतंक के आकाओं को चेतावनी है कि भारतीय नागरिकों की जान से खेलने का अंजाम विनाशकारी होगा। अब वार करते हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की, जो नक्सलवाद के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। मई 2025 में छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर शुरू हुआ यह 24-दिवसीय अभियान, करेगुट्टालु पहाड़ियों जैसे नक्सली किलों को लक्ष्य बनाया गया। नक्सलवाद, जो दशकों से आदिवासी क्षेत्रों में विकास को बाधित कर रहा था, अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है।

सुरक्षा बलों ने 31 कुख्यात माओवादियों को मार गिराया, जिनमें टॉप लीडर बसवराजू जैसे नाम शामिल थे, जिन पर कुल 1.72 करोड़ रुपये का इनाम था। इसके अलावा, 214 नक्सली ठिकाने और बंकर ध्वस्त किए गए, 450 आईईडी, 818 बीजीएल शेल और 899 कोडेक्स बंडल जब्त किए गए। यह ऑपरेशन न केवल सैन्य दृष्टि से सफल रहा, बल्कि यह नक्सलवाद के 'यूनिफाइड कमांड' को तोड़ने में भी कारगर साबित हुआ। देश-विरोधी ताकतों को धूल चटाने का यह अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नक्सली लंबे समय से 'रेड टेरर' फैला रहे थे। वे विकास परियोजनाओं को नष्ट करते, निर्दोष ग्रामीणों को निशाना बनाते और सरकार को कमजोर दिखाने का प्रयास करते। लेकिन ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने इन तत्वों की कमर तोड़ दी। 27 से अधिक विद्रोहियों की मौत, जिसमें शीर्ष कमांडर शामिल थे, ने नक्सल नेटवर्क को चिखड़ित कर दिया। अब करेगुट्टालु पहाड़ियों पर तिरंगा लहरा रहा है, जो माओवादी किले से शांति का प्रतीक बन गया है। सीआरपीएफ महानिदेशक ने इसे 'नक्सलवाद के अंत की शुरुआत' बताया, जो सही मायने में सत्य है। इन परिणामों से न केवल आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई, बल्कि आदिवासी समुदायों में विकास का द्वार खुला है। स्कूल, अस्पताल और सड़कें अब बिना डर के बन सकेंगी, जो नक्सलियों की सबसे बड़ी हार है। इन दोनों अभियानों की सफलता का श्रेय निस्संदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। ऑपरेशन महादेव और ब्लैक फॉरेस्ट ने देश-विरोधी ताकतों को पूरी तरह धूल में मिला दिया है। आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी चुनौतियां अब इतिहास का हिस्सा बन रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और गृह मंत्री शाह की रणनीतिक कुशलता ने इन सफलताओं को संभव बनाया। यह विजय न केवल सुरक्षा बलों की बहादुरी का सम्मान है, बल्कि पूरे राष्ट्र की एकता का प्रतीक भी। भविष्य में, ऐसे अभियान जारी रहेंगे, और भारत एक सुरक्षित, समृद्ध राष्ट्र के रूप में चमकेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

वार्ता से निकल सकता है हर समस्या का हल

संकलित
दर्शन

वार्ता से प्रत्येक व्यक्ति का सरोकार है। जब मन में संदेह उपजे, हृदय अविश्वास से घिर जाए, मस्तिष्क में विचार न ठहरे, तब वार्ता से ही रास्ता निकलेगा। कोई भी विवाद हो, कैसी भी समस्या हो, फिर भी वार्ता से हल निकल सकता है। संबंधों में कितना भी ठहराव क्यों न आ जाए, लेकिन वार्ता के ताप से रिश्तों पर जमा बर्फ भी पिघल जाती है। वार्ता में शिथिलता के लिए केवल अहंकार दोषी होता है। किसी भी विध्वंस का कारण अहंकार ही रहा है। विश्व शांति की अवधारणा परस्पर संवाद पर ही टिकी है। संवादहीनता से कूटनीति और राजनीति अकेली पड़ सकती है। बातचीत चलती रहे तो विकल्प निकलने की संभावना बढ़ जाती है। चर्चाओं में तर्क, सुझाव और मतों का विभाजन होता रहता है। यह अनवरत प्रक्रिया है। जनता के मध्य निरंतर जनमत पर चर्चा चलती रहती है। लोक चर्चा और लोकमत से संसार की बड़ी समस्याओं पर सकारात्मक निष्कर्ष निकल सकते है। चर्चा या वार्ता को प्रोत्साहित करना उचित है। संवादहीनता को हतोत्साहित करना चाहिए। सभी द्वार भले ही बंद हो जाएं, लेकिन बातचीत का द्वार सदैव खुला रहे। लोग कहते हैं कि पैसों का काम पैसों से ही चलता है, बातों से नहीं। यह बात सच है कि बातों से कोई काम नहीं होता, काम तो काम करने से ही सकता है, लेकिन काम तभी हो सकता है, जब उस काम से पहले कोई विचार स्थिर हो। विचार स्थिर होगा तो उससे संबंधित बात पूरी हो सकेगी और बात होगी तो काम का आदेश होगा। काम का आदेश स्वयं या अन्य प्रकार का हो सकता है।

हे श्री कृष्ण! तुम सर्वज्ञ हो

संकलित
प्रेरणा

एक वृद्ध महिला एक सब्जी की दुकान पर जाती है, उसके पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते है। वो दुकानदार से प्रार्थना करती है कि उसे सब्जी उधार दे दे पर दुकानदार मना कर देता है। उसके बार-बार आग्रह करने पर दुकानदार खीज कर कहता है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, जिसकी कोई कीमत हो, तो उसे इस तराजू पर रख दो, मैं उसके वजन के बराबर सब्जी तुम्हे दे दूंगा। वृद्ध महिला कुछ देर सोच में पड़ जाती है। क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद वह, एक मुट्ठा-तुड़ा कागज का टुकड़ा निकालती है और उस पर कुछ लिख कर तराजू पर रख देती है। दुकानदार ये देख कर हंसने लगता है। फिर भी वह थोड़ी सब्जी उठाकर तराजू पर रखता है। आश्चर्य..!!! कागज वाला पलड़ा नीचे रहता है और सब्जी वाला ऊपर उठ जाता है। इस तरह वो और सब्जी रखता जाता है पर कागज वाला पलड़ा नीचे नहीं होता। तंग आकर दुकानदार उस कागज को उठा कर पढ़ता है और हैरान रह जाता है। कागज पर लिखा था, हे श्री कृष्ण! तुम सर्वज्ञ हो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दुकानदार को अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उतनी सब्जी वृद्ध महिला को दे देता है। पास खड़ा एक अन्य ग्राहक दुकानदार को समझाता है, कि दोस्त, आश्चर्य मत करो। केवल श्री कृष्ण ही जानते हैं की प्रार्थना का क्या मोल होता है। वास्तव में प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। चाहे वो एक घंटे की हो या एक मिनट की। यदि सच्चे मन से की जाए, तो ईश्वर अवश्य सहायता करते है।

अंतर्मन

आज की पाती

भारत की कैसी ऋण प्रणाली

हीरा कारोबारी भगोड़े मेहुल चौकसी को बेल्जियम से वापस लाने के लिए भारत की तमाम जांच एजेंसियां ने पूरा जोर लगाया हुआ है। मेहुल चौकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक में लगभग 13500 करोड़ का घोटाला किया हुआ है। अब यह भारत की कैसी ऋण प्रणाली है जिसमें चौकसी और मोदी जैसे बड़े-बड़े कारोबारियों को बड़ी ही आसानी से बैंकों से ऋण प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर उन्हीं बैंकों से किसी आम नागरिक, किसान या गरीब व असहाय व्यक्ति ने अपने जीवन को सुधारने के लिए ऋण की नाममात्र रकम ही क्यों न लेनी हो, उससे सैकड़ों औपचारिकताएं पूरी करवाने के साथ-साथ गारंटर भी मुहैया करवाना पड़ता है। लेकिन ये बड़े कारोबारी हमेशा सरकारों और बड़े नेताओं के करीबी होने का फायदा उठाते हैं और इन पर वाजिब कार्रवाई भी नहीं हो पाती।

– सतीश एच्छल, कांकेर

ट्रेंड

चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

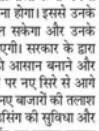

एक लंबा समय था जब ब्रिटिश और डचों की एक लंबा समय नहीं है। मोदी जी ने यह दिखाया कि कैसे गरीबों का कल्याण और आर्थिकसत्ता का उत्थान सामानांतर चलता है। उनके नेतृत्व में भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है।

- अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

सिकल सेल एनीमिया

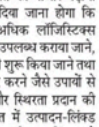

हमारे जनजातीय बहुल इलाकों में सिकल सेल एनीमिया एक बहुत बड़ा खतरा होता है। हमारी खतरंक जनजातीय भाई-बहनों को इस बीमारी से बचाने के लिए राष्ट्रीय मिशन चला रही है। आज लाखापेटा में ही सिकल सेल तकनीक का 1 करोड़वां कार्ड वितरित हुआ है।

- जेपी नड्डा, सीएम, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार

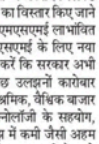

'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान परिवार, समाज और राष्ट्र की मजबूती का आधार है। आज देशभर स्वास्थ्य शिविरों में अनुमिया पेरेल की उपस्थिति में दिल्ली से भी इस अभियान का शुभारंभ किया।

-रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

बेहद निंदनीय

सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने तथा बच्चियों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आजीवन कार्य करने वाले समाज सेविका फुले के पेंटर को राजस्थान यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स सहित पाठ्यक्रम से हटाया जाना बेहद निंदनीय है।

-अशोक गहलोत, पूर्व सीएम, राजस्थान

करंट अफेयर

दुनिया संकट के कगार पर शांति पर निवेश करना होगा

वैश्विक सुरक्षा संकेतक स्पष्ट रूप से बताते हैं कि शांति और स्थिरता की स्थिति में गंभीर गिरावट आई है। अधिकांश रिपोर्टों के अनुसार, आज की दुनिया हाल के इतिहास में कहीं अधिक हिंसाग्रस्त और खतरनाक बन चुकी है। साल 2024 में, विश्वभर में राज्य-आधारित संघर्षों की संख्या 1946 के बाद अपने सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई है। लगातार दस वर्षों से सैन्य खर्च बढ़ रहा है और यह वार्षिक 2.7 खरब अमेरिकी डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है। सशस्त्र संघर्षों के पीड़ित बच्चों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जबकि महिलाओं के अधिकारों पर भी वैश्विक स्तर पर खतरा है। विश्व आज कई जटिल संकटों का सामना कर रहा है। सितंबर 2024 में, संयुक्त राष्ट्र ने 'समिट फॉर द फ्यूचर' का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के बाद बहुपक्षीय प्रणाली के पतन, बढ़ती संघर्ष स्थितियों और मानवीय आपदाओं से निपटने पर चर्चा करना था। ये सभी संकट जलवायु परिवर्तन के युग में उभर रहे हैं। ये संकट आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि बढ़ती गर्मी और सूखे की स्थितियों के कारण हिंसा की आशंका बढ़ जाती है। इसके साथ ही, सैन्य बल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और पर्यावरणीय क्षति में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो कभी-कभी पर्यावरणीय अपराध के रूप में देखा जाता है।

ऑफ बीट

अपच आम बात है पर ये कभी-कभी चिंताजनक भी

मानव शरीर में पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है- ऊपरी और निचला। ऊपरी पाचन तंत्र में मुंह, ग्रासनली, इसोफेगस (अन्ननली), पेट और छोटी आंत का पहला भाग डिऑडेनम शामिल होता है। इन हिस्सों से जुड़ी समस्याओं में आमतौर पर डिस्पेप्सिया (अपच) शामिल है, जिसमें पेट फूलना, डकार आना, मतली और भारीपन जैसी शिकायतें देखी जाती हैं। यह स्थिति अम्लता, रिफ्लक्स या वॉटरब्रेश यानी गले में कड़वाहट के रूप में भी सामने आ सकती है। बाजार में अपच से राहत देने वाली कई दवाएं उपलब्ध हैं जैसे कि पेप्टो-बिस्मोल, गैविस्कॉन (जो पेट की अम्लीय परत पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है), और रैनी जैसी चबाने वाली टैबलेट। ओमेप्राजोल जैसी एसिड-घटाने वाली दवाएं भी बिना डॉक्टर के पर्चे के मिलती हैं, लेकिन लंबे समय तक इनका इस्तेमाल गंभीर बीमारियों की पहचान में देरी कर सकता है। अपच के संभावित कारण : तेज मसालेदार भोजन, पेट का संक्रमण, हाइटस हर्निया, गर्भावस्था, मोटापा, धूमपान और कुछ दवाएं (जैसे कि आईबुप्रोफेन, एंटीडिप्रेसेंट्स, आयरन टैबलेट्स) अपच का कारण बन सकती हैं। कुछ मामलों में यह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण भी होता है, जो पेट की परत में रहकर अल्सर का कारण बन सकता है।

हमारा पता
हरिभूमि कार्यालय
नजदीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, रोहतक-124001 फोन: 9253681019-20
ई-मेल : haribhoomi@gmail.com
वेब-साइट : www.haribhoomi.com

राहुल पाण्डेय
शोधार्थी, पूर्वी एशियाई अध्ययन केंद्र, जेएनयू

आजकल

भारत-रूस व्यापार और अमेरिकी टैरिफ

अमेरिकी टैरिफ लागू होने के मात्र चार दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) समिट में भागीदारी ने संदेश दिया कि भारत ने अपने विकल्पों को खुला रखा है। सात साल बाद हुई इस चीन यात्रा में मोदी और विनफिंग की मुलाकात ने भारत-चीन रिश्तों में एक नई शुरुआत की उम्मीद पैदा की। एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 45 मिनट की विशेष बातचीत की, वह भी पुतिन की गाड़ी में बैठकर। यह प्रतीकात्मक क्षण था जो दिखाता है कि भारत रूस को दरकिनार नहीं कर सकता

हाल ही में चीन में आयोजित एससीओ सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। साथ में चीन एवं रूस के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं। पाञ्चट

बीते माह अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ प्रभावी हो गया और इसके कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सात वर्षों में पहली बार चीन की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मंच साझा करते दिखे। मोदी ने पुतिन के साथ कार में 45 मिनट तक एकांत बातें भी कीं। टैरिफों का आधा हिस्सा भारत का रूस के साथ व्यापार करने की सजा के रूप में लगाया गया है। यह स्पष्ट संकेत था कि भले ही भारत के पास दुर्लभ खनिजों जैसे रणनीतिक संसाधन न हों, उसके पास मजबूत कूटनीतिक विकल्प मौजूद हैं।

भारत-चीन-रूस की त्रिपक्षीय बैठकों में यह संकेत दिया गया कि भारत बहुध्रुवीय विश्व में संतुलन स्थापना चाहता है। भारत न तो पूरी तरह पश्चिम के साथ खड़ा है, न ही पूरी तरह रूस-चीन धुरी के साथ। यह 'स्ट्रैटेजिक आटोनामी' का वही सिद्धांत है जिसने भारत की विदेश नीति को दशकों तक परिभाषित किया है। रूस के साथ व्यापार करने का भारत का निर्णय व्यावहारिकता पर आधारित था। भारत आज ऐसी जटिल कूटनीतिक और आर्थिक स्थिति में है जहां हर निर्णय के वैश्विक असर हैं और भारत की अपनी महत्वाकांक्षाएं जो कि विकसित भारत के सपनों को साकार भी कर सकती हैं और धूमिल भी। एक ओर रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा व्यापार है, तो दूसरी ओर अमेरिका के साथ गहरे आर्थिक रिश्ते। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा आर्थिक व्यापार करने वाला देश है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ ने नई दिल्ली की रणनीतिक गणना को कठिन बना दिया है। आधा टैरिफ रूस के साथ भारत के व्यापार को लेकर सजा के रूप में देखा जा रहा है।

व्यावहारिक निर्णय : मूलरूप से हम आर्थिक आधार पर ही ध्यान दें तो रूस के साथ भारत का बढ़ता ऊर्जा व्यापार काफी हद तक व्यावहारिक निर्णय है। वर्ष 2022 में शुरू हुए रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस से दूरी बना ली, भारत ने अवसर देखा और रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। उस समय रूसी तेल ब्रेंट क्रूड से 20-35 डालर प्रति बैरल सस्ता मिल रहा था। यह छूट धीरे-धीरे घटकर आज तीन-चार डालर रह गई है। फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह बचत महत्वपूर्ण है।

भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक आफ इंडिया के आकलनों के अनुसार यदि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो उसका वार्षिक तेल आयात बिल 9-12 अरब डालर तक बढ़ जाएगा। यह भारत की जीडीपी का लगभग 0.2 से 0.3 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त रूस भारत को हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। 2019 से 2023 के बीच भारत के कुल हथियार आयात का 36 प्रतिशत रूस से आया।

रक्षा मंत्रालय के आधुनिकीकरण बजट के आधार पर अनुमान है कि भारत हर साल लगभग 1.6 अरब डालर रूसी हथियारों पर खर्च करता है। यदि भारत वैकल्पिक स्रोतों से हथियार खरीदे तो लागत तीनगुनी भी हो सकती है, लेकिन कुल अतिरिक्त भार जीडीपी के लिहाज से बहुत बड़ा नहीं होगा। यानी रूस से दूरी बनाने का कुल आर्थिक असर 0.2 से 0.3 प्रतिशत जीडीपी के बीच होगा। यह प्रबंधनीय लागत है, लेकिन इसका भू-राजनीतिक असर गहरा हो सकता है, क्योंकि रूस न केवल ऊर्जा सप्लायर है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का पुराना मित्र भी है।

अमेरिकी टैरिफ का असर : अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए सेंधी चुनौती है। अमेरिकी आयात में भारत का योगदान 2024 में 86.5 अरब डालर का था, जिसमें से 48.5 अरब डालर के निर्यात टैरिफ के दायरे में हैं। यदि इन पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू रहते हैं तो भारतीय जीडीपी पर 0.3 से 0.6 प्रतिशत का बोझ पड़ेगा। यह बोझ रूस से दूरी बनाने की लागत से अधिक है। इसके अतिरिक्त भारत में कपड़ा उद्योग, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में काफी हद तक रोजगार पर गहरा असर पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत सरकार आर्थिक गणना कर रही है कि क्या रूस से व्यापार जारी रखना आर्थिक रूप से उतना लाभकारी है जितना अमेरिकी टैरिफ हटाना हो सकता है? यदि रूस से दूरी बनाने पर अमेरिका टैरिफ घटाकर 25 प्रतिशत कर दे तो जीडीपी पर असर आधा रह जाएगा। यानी शुद्ध आर्थिक लाभ लगभग संतुलित हो जाएगा।

दिलचस्प यह है कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनकी 75वीं जन्मतिथि पर फोन कर शुभकामनाएं दीं। यह इशारा है कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच संवाद पूरी तरह टूटा नहीं है। मंगलवार को भारत और अमेरिकी व्यापार से संबंधित लोगों के बीच काफी सक्रिय और सकारात्मक जानकारी सामने आई जो कि दोनों देशों के बीच में व्यापार मतभेदों को लेकर सकारात्मक संदेश है। अमेरिका-भारत संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, वे प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग और हिंद-प्रशांत रणनीति पर भी टिके हैं। इसलिए संभव है कि आने वाले महीनों में दोनों देश किसी ऐसे समझौते पर पहुंच जाएं, जिससे पुख्ता निष्कर्ष निकल सके।

आज भारत के सामने दो बड़े विकल्प है : रूस से दूरी बनाकर अमेरिकी टैरिफ में राहत पाना और रूस के साथ व्यापार जारी रखकर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, लेकिन अमेरिकी दबाव झेलना। आर्थिक गणना कहती है कि दोनों विकल्प लगभग बराबर हैं। लेकिन कूटनीति केवल गणित नहीं है। भारत को यह ध्यान रखना होगा कि ऊर्जा सुरक्षा दीर्घकालिक प्राथमिकता है। साथ ही अमेरिका के साथ तकनीकी और रक्षा सहयोग भी महत्वपूर्ण है।

मौदी सरकार का प्रयास यही होगा कि दोनों मोर्चों पर संतुलन बना रहे। आने वाले महीनों में भारत अमेरिकी टैरिफ में कमी के लिए रूस से आंशिक दूरी बनाता है या फिर 'मल्टी-अलाइनमेंट' की नीति को और आक्रामक रूप से आगे बढ़ाता है। भारत की ताकत यही है कि वह किसी एक खेमे में बंधा नहीं है। यही नीति आने वाले वर्षों में भारत को आर्थिक और भू-राजनीतिक रूप से और सशक्त बना सकती है।

ट्रंप के प्रति पूरी सावधानी बरते भारत

डा. अनिता राठौर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत को अत्यंत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ वह जहां शंघाई कापरेशन बैंकक में मोदी के जाने के बाद से उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त बता रहे हैं और भारत तथा अमेरिका के मजबूत रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं। सच ही यह भी कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार डील बस होने ही वाली है। वहीं दूसरी तरफ चुपके चुपके जी-6 देशों यानी फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान और यूरोपीय यूनियन को अपने ढंग से उकसा भी रहे हैं कि भी भारत पर भारी से भारी टैक्स लगाएं, जिसमें उनका सुझाव भी प्रतिशत तक टैक्स लगाए जाने का है। भला यह कौन सी दोस्ती और कौन से मजबूत रिश्तों का फर्ज है कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त पर कुछ देशों को भारी टैक्स लगाने के लिए उकसा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप बहुत अस्थिर मनःस्थिति के राजनेता हैं। दरअसल ट्रंप हमेशा से स्वयं को एक बिजनेस मैन और डील मास्टर के रूप में पेश करते रहे हैं, इस पर उन्हें गर्व महसूस होता है। उनको लगता है कि दुनिया केवल कारोबार से चलती है। इसलिए उनकी यह कोशिश रहती है कि हर संबंध में वह जिस सौदे पर हाथ डालें, वह पूरी तरह से खरा सौदा साबित हो। लेकिन भारत को लेकर उनका आकलन गड़बड़ा गया है। वह जिस आसानी से मान बैठे थे कि भारत उनकी एक धुड़की के बाद सरेंडर कर देगा और हाथीताथ अमेरिका की मर्जी के मुताबिक डील हो जाएगी, वह दूर दूर तक कहीं नहीं हुई और इससे ट्रंप ने केवल झुंझला गए हैं, बल्कि अपनी समूची ताकत से भौखलाने के बाद अब ठंडे दिमाग से इसे नई रणनीति के जरिये सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि वह भारत से दोस्ती का गलबहियां डालकर हमें बिश्वास दिलाएं कि दुनिया में एकमात्र भरोसेमंद भारत का कोई दोस्त है, तो वह ट्रंप है और इसी बीच वे अपने जी-7 के शेष सहयोगी पर यह दबाव डाल रहे हैं कि वे भारत पर इतना टैरिफ लग दें कि उसे अमेरिका की शरण में आना पड़े।

सारे विश्लेषण खराब से खराब स्थिति में आकलन करके देख चुके हैं कि ट्रंप और अमेरिका की सारी उठापटक के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में 0.5 से 0.6 प्रतिशत के बीच ही कोई कमी आ सकती है। अगर अमेरिका की इस टैरिफ कढ़ाई से सबसे ज्यादा हमें प्रभावित किया, तब। और हां, इसके साथ ही यह बात भी अब खुलकर सामने आ गई है कि भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के हमसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को होने शुरू हो चुके हैं। अमेरिका में 0.5 प्रतिशत तक की मुद्रास्फीति नजर आने लगी है और यही कारण है कि अमेरिकी कारोबारियों का ट्रंप पर लगातार दबाव बढ़ रहा है कि वे भारत के साथ टैरिफ नीति पर किसी सकारात्मक निर्णय तक पहुंच जाएं।

वस्तुतः ट्रंप का भारत से मीठी बातें करना, उनकी रणनीति का हिस्सा है, ताकि भारत का उन पर भरोसा बना रहे और कठोर दबाव डालना उनकी शैली है, ताकि भारत झुकने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन उनकी यह रणनीति भारत के सेंधमें तो नहीं चलने वाली। आज दुनिया में कोई भी देश इस सोच के साथ कि भारत को साथ भी रखो और हर सौदे में उसे जमकर निचोड़ो, इस मंशा से भारत के साथ न भरोसा कायम कर सकता है, न दोस्ती और न किसी तरह की साझेदारी। इसलिए ट्रंप को भी ऐसा कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन ट्रंप को यह समझ में आए, इसके लिए भारत को रणनीतिक तौर पर सबधान रहने की जरूरत है।

(लेखिका आर्थिक विश्लेषक हैं)

खरी-खरी

आसान नहीं नेतागिरी

सुनीत जैन राही

राजनीति उसे करनी चाहिए, जिसका नेटवर्क चूहों की भांति सशक्त और बिल खोदने में मजबूत हो। जो अंदर से खोखला कर सके और बाहर से सब झीकठाक लगे। राजनीति में कुर्सें पर बैठने के बाद उसे बचाए रखने की सज्जिश में माहिर हो। झम्मन का नेटवर्क चूहों से बेहतर था। वे उन्हें खोखला करते, जिनसे खतरा महसूस होता। इसे नेटवर्क का कमाल था कि समाज ने उन्हें नया नाम दे दिया। वे बाबूजी से हो गए। झम्मन बाबूजी में कैसे बदले? क्यों बदले? कब बदले? कोई नहीं जानता? जिसने भी होश संभाला बाबूजी ही पाया।

बाबूजी एक सामान्य कद-काठी के बाबूजी दिमाग के धनी थे। वे खरबूजे के समान थे। भीतर से मीठे, ज्यादा खाने से दस्त लगना तय। बाबूजी शकुनें मामा से कम नहीं। कौन समझ पाया? उचकने (बिहीर की आशंका) वाले युवाओं के कंधे पर हाथ रखा। बुलाकर पूरा सहयोग देने का आश्वासन दे डाला। कहा- जो मदद चाहिए बता देना। अपने घर की बात है। एक दिन गजब कर दिया। युवाओं की सभा में बिना बुलाए जा पहुंचे। बाबूजी ने सबकी ध्यान से सुना, कहा कुछ नहीं। सभा समाप्त होने पर कहा- मेरे खून की हर बूंद तुम्हारे लिए है।

बाबूजी ने सबसे पहले उन छोरों को घेरा जिनके हाथ में कमान थी। फिर उनके घर की जड़ों में मट्ठा डालना शुरू किया। बरगद की मजबूती उसकी जड़ों पर निर्भर रहती है। बाबूजी ने छोरों के बाप को दिए कर्ज की उगाही में तेजी लानी शुरू कर दी, जिससे घर वालों का उनकी नेतागिरी से मन भर गया। फिर कर्ज उतारने के लिए दबाव बनने लगा। अब कुछ तो काम करना पड़ेगा। छुट्टे सांड़ों की तरह घूमने वाले बंधे गाय की तरह दूध देने के लिए मजबूर हो गए। युवाओं की सभा में दो-चार बूढ़ों के अलावा और कोई नहीं दिखाई देता। बुढ़ऊ की मिलने वाली पोंक की पिलिस और बोही बंद हो गई तो उन्होंने जाना छोड़ दिया। फिर से बाबूजी की शरण में।

कुर्सी उसे ही मिलती है, जिसने मक्कारी की फसल काटी हो। नेतागिरी वही करता है, जिसका पेट छाती से बाहर हो और जिसकी पसलियां दिखाई दे रही हों उसे तो वोट देकर कर्तव्य निभाना चाहिए।

पोस्ट

आपका हुनर आपको अपने क्षेत्र में बुलंदी तक तो पहुंचा सकता है, पर आप वहां कितनी देर तक टिक पाएंगे, यह अहंकार व्यवहार पर निर्भर करता है।

रजत शर्मा@RajatSharmaLive

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने एक मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से ही कह दिया कि आप भगत हैं तो भगवान विष्णु से जाकर ही कहिए कि वही कुछ करें। वे चाहते तो ऐसी वाहियात याचिका को खारिज कर सकते थे। इससे हिंदू-मुस्लिम विवाद का प्रपंच ही नहीं था।

प्रभाकर मिश्रा@PMishra_Journo

सीपीआइ-माओवादी द्वारा आत्मसमर्पण का दांव एक प्रपंच है। अपने जाल में फंसे सरकार से यही चाहते हैं कि उनके खिलाफ चल रहे अभियान पर विराम लगा दिया जाए। इस मौके का फायदा वे खुद को नए सिरे से मजबूत बनाने पर करेंगे, जो हाल में तमाम माओवादियों को गंवा चुके हैं। बेहतर यही होगा कि सरकार अधूरा काम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित रखे।

मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

जागरण जनमत

क्या मैच रेफरी पर कार्रवाई से आक्रामकता का इन्कार पाकिस्तान के मुंह पर उगाना है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज तक सवाल

क्या भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की बाधाएं दूर होती दिख रही हैं?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

बच्चे गेमिंग एप पर लगा रहे हैं दांव,
एक बार यदि घुस गए धंसते जाते पांव।
धंसते जाते पांव बाप का माल लुटाते,
जब जाते धन हार ममीत की गले लगाते।
बनि पांडव के पूत खेलकर खाते गच्चे,
जुआ खेल वर्वाद हो रहे एक रेचबच्चे!

- ओमप्रकाश तिवारी

मध्य प्रदेश डायरी

धार से आदिवासियों को अपनेपन का संदेश

धनंजय प्रताप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, नईदुनिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी जन्मतिथि पर बुधवार को मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिले में आए। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली चार जन्मतिथियों (17 सितंबर) में से दो मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में मनाकर देशभर के आदिवासियों को अपनेपन का संदेश दिया है। 17 सितंबर, 2022 को भी प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल ब्योपुर के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए आठ चीतों को छोड़ा था। अब इस जन्मतिथि पर उन्होंने धार के धैसोला में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। दोनों कार्यक्रम बड़े थे और संदेश इससे भी बड़ा रहा।

आदिवासी बहुल जिला धार गुजरात की सीमा के करीब ही है। गुजरात के उद्योग, छोटा उदयपुर जैसे क्षेत्र की आदिवासी संस्कृति और मालवा-निमाड़ के भील आदिवासी आपस में रोटी-बेटी का संबंध रखते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अपनी जन्मतिथि पर इस अंचल में पहुंचकर देशभर के आदिवासियों को एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। झाबुआ जिले के प्रसिद्ध अंगवस्त्र आदिवासी सारली यानी दुपट्टा गले में डालकर एकदम सकारात्मक और उत्साह से भरे माहौल में पीएम मोदी ने देशज स्टाइल में जो कुछ कहा, वह समूचे देश के आदिवासियों को एकजुट रखने का प्रयास है।

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जन्मतिथि के अवसर पर आदिवासियों के बीच आकर कांग्रेस के उस कथित षड्यंत्र का जवाब दिया है जिसके तहत वह आदिवासियों को हिंदुओं से अलग करना चाहती थी। कुछ ही दिनों पहले धार जिले के ही निकसी और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा था कि गर्व से कहो आदिवासी हिंदू नहीं। कांग्रेस ने उमंग सिंघार के इस बयान से स्वयं को अलग नहीं किया, इसका आशय यही है कि कांग्रेस का भी उद्देश्य आदिवासी वर्ग को हिंदुओं से अलग बताना है। कांग्रेस ने यह विषय उस समय उठाया, जब जनगणना शुरू होने वाली है। कांग्रेस आदिवासियों को बरगलाकर जनगणना में उन्हें हिंदुओं से अलग दर्जा दिलाना चाहती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण के शुरू में भारत माता के साथ नर्मदा मैया का जयकारा लगाया। साथ ही मां वाग्देवी और भगवान विश्वकर्मा को प्रणाम किया। मालवा-निमाड़ से लेकर गुजरात तक के आदिवासियों की मां नर्मदा के प्रति गहरी आस्था है। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्या बाई को भी याद किया। वस्तुतः देवी अहिल्या बाई और भीलों का भी भावनात्मक रिश्ता रहा है। नारी शक्ति, गरीब, युवा और किसान की विकसित भारत के चार स्तंभ बताते हुए इन्हें राष्ट्र की प्रगति का आधार बताया। इसे आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि आदि सेवा पर्व का मध्य प्रदेश संस्करण आरंभ हो रहा है, जो जनजातीय समाज की योजनाओं से जोड़ने का सेतु बनेगा। अभियान 'स्वस्थ नारी- सशक्त परिवार' की शुरुआत के पीछे यही भाव छिपा है कि आदिवासी वर्ग सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। प्रदेश के आदिवासी इलाकों में सिकल सेल एनीमिया बड़ी समस्या है। हमारी सरकार इस बीमारी से बचाने के लिए राष्ट्रीय मिशन चला रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया कि इस मिशन की शुरुआत भी मध्य प्रदेश के शहडोल से हुई थी। यह भी कहा कि सिकल सेल स्क्रीनिंग का एक करोड़वां कार्ड भी इसी धरती से मेरे हाथों से दिया गया है। इससे आने वाली पीढ़ी भी आशीर्वाद देगी। आदिवासी माताओं-बहनों से आग्रह भी किया कि सिकल सेल की जांच अनिवार्य रूप से कराएं।

धार में आयोजित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभा में आदिवासी समुदाय की महिलाएं। नईदुनिया

आदिवासी भाइयों से भी पीएम मोदी ने सख्त मांग और कहा कि वे महिलाओं को स्वस्थ रखने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी गुजरात के आदिवासी वर्ग से हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया से आदिवासी वर्ग को निजात दिलाने के लिए प्रयास आरंभ किए थे। प्रधानमंत्री के धार आने की बड़ी वजह आदिवासी वर्ग से निकटता भी है। आने वाले चुनाव में भी इस वर्ग की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगी। पैसे में यह भी कहा जा सकता है कि इस दृष्टिकोण से भी धार का चयन किया गया।

धार में आदिवासी समुदाय से करीबी और दूसरी तरफ पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करके प्रधानमंत्री ने बिखरते से विकास का संदेश दिया है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव का नारा 'मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी' को भी चरितार्थ किया।

हिमाचल प्रदेश डायरी

अब तो रास्ता बदलोगे न हिमाचल प्रदेश?

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक,
हिमाचल प्रदेश

एक सामान्य व्यक्ति रात को परिवार के साथ सोया है... अगले दिन के कार्यों के बारे में विचार करते हुए। बादल फटने, भूस्खलन और धंसकने के कुछ ही पलों के बाद सब अतीत हो जाता है। न घर बचता है, न ही घर वाले। कोई वाहन चलाते हुए जा रहा है, अचानक गोली की गति से पत्थर उतरता है और वाहन टुकड़ों में बंटकर खाई में चला जाता है। इन दुस्कर्मों को 90 दिन यानी तीन माह से झेलता आ रहा हिमाचल प्रदेश यह नहीं समझ पा रहा है कि जीवन का पुनः आरंभ कहां से किया जाए। लेकिन उठना तो होगा। उठे बिना गुजारा नहीं है।

ठीक है, पर उठें कहां से? हिमाचल प्रदेश सरकार ने उठने की शुरुआत संभवतः उस बिंदु से की थी, जब उस भू-भाग को संरक्षित घोषित किया था, जिसे एक कंपनी होटल बनाने के लिए मांग रही थी। वह बिंदु और है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा और मंत्रिमंडल ने भी मोहर लगा दी कि कोई भी निर्माण अब नदियों-नालों से 50 से 100 मीटर दूर ही हो पाएगा। स्थानीय पंचायतों की अनापत्ति भी अनिवार्य की गई है। एक शुरुआत मंडी जिले के धर्मपुर से हुई है जहां सौन खड्ड में किसी की जिद की नींव पर बस अड्डा कई वर्ष पूर्व बना दिय गया था। दो दिन पहले 18 से 20 बसें अड्डे में बह गई थीं। हानि के आंकड़े सार्वजनिक हैं, वर्ष के आंकड़े सबको पता हैं, यह बिसरी भी आम ही गया है कि हिमाचल समेत अन्य पहाड़ी राज्यों की आपदा कितनी प्राकृतिक और कहां तक अप्राकृतिक है। अगर यह आपदा प्राकृतिक है तो प्रकृति की बात सुननें चाहिए। धर्मपुर वस्तुतः एक केस स्टडी है कि कैसे खड्ड में बस अड्डा बन दिया गया। स्थल चयन समिति से लेकर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के तत्कालीन अधिकारी, वन विभाग, हिमुडा... सब के सब किसी प्रभावी जिद के आगे बौने पड़ गए थे। वर्तमान सरकार को अड्डा ही स्थानांतरित करना पड़ रहा है तो स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए।

कांगड़ा हवाई अड्डा एक पहाड़ी पर है। इस पहाड़ी के नीचे पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग है। अप्राकृतिक एक धारा पानी की निकली और कितना ही मलबा अब तक निकाला जा चुका है। पहाड़ को छांटता हुआ यह स्खलन हवाई अड्डे की बाड़ तक पहुंच गया है। लोगों को हो रही परेशानी, यातायात जाम एक बात है, किंतु एक और पहाड़ी में आई दरार है, दूसरी ओर खड्ड (छोटी नदी) है। हिमाचल प्रदेश की परंपरा में रहे हैं प्याऊ। यह सरि या धाराएं जहां-जहीं फूटती हैं, वाहनों वाले, पैदल चलने वाले प्यास बुझाते थे। यह सबक पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए भी है कि कंक्रीट की नींव में दबा कर प्राकृतिक स्रोत नहीं दबते। आप फोरलेन बनाइए, सुरंगें बनाइए, पुल बनाइए, लेकिन पानी को मत मारिए, वरना पानी बख्श ले जाएगा।

जब पानी की एक धारा इतना नुकसान कर सकती है तो सौन खड्ड ने धर्मपुर के कि राजनीतिक व्यक्ति को यह आश्वासन दिय था कि वह पुनः रौद्र रूप धरण नहीं करेंगे? बस क्षेत्रीयता और लोकप्रियता के आगे मानकों को भी पानी में डुबो देना चाहिए था? जांच भी हुई थी, कार्रवाई की अनुशंस भी, किंतु हुआ कुछ नहीं। सुक्खू सरकार सख्त निर्णय ले रही है, वह चाहे तो डेढ़ दशक पुराने इस मामले की जांच भी कर सकती है।

प्रकृति की बात सुनने और उसके सम्मान का एक ढंग यह भी हो सकता है कि पुरानी भवन निर्माण शैली को और लौटें। पहाड़ों पर भीड़ न बढ़ाएं। पानी को रास्ता दें। नदियों की गोद में होम स्टे, होटल आदि के मोह से बचें। बरसतें में हर झरने को नाला, नाले को खड्ड और खड्ड को नदी बनने में किसी की अनुमति नहीं चाहिए। हरियली को शत्रु न समझें। पर्वतीय राज्यों में रहने वाले लोगों को भी समझना होगा कि वे हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश ही बना रहने देना चाहते हैं या नहीं। मैदानें वाली सुविधाएं इसी प्रकार पहाड़ों पर जुटाने की होड़ जारी रही तो पहाड़, मैदान बन जाएंगे, पहाड़ नहीं रहेंगे।

हिमाचल प्रदेश का शिक्षा विभाग और शिक्षा बोर्ड इस बात पर भी विचार करें कि नैतिक शिक्षा और योग जितना ही आवश्यक अब यह विषय भी होना चाहिए कि पहाड़ और पर्यावरण के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। जो सूरज ढलने के बाद हरा पत्ता न तोड़ने पर कभी अपराध बोध अनुभव करते रहे हिमाचल प्रदेश को लौटना चाहिए अब। जल को प्रदूषित न करने या उसका बहाव बंद न करने वाले हिमाचल प्रदेश की आवश्यकता है अब। जब सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरा हिमालय क्षेत्र ही खतरे में है तो इसका कोई अर्थ है। नगर एवं ग्राम नियोजन को परेशरगत स्थापनओं से सेंस्कन चाहिए।

पहले लोग पूछते थे- आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं? जवाब होता था- जी हां! पलट कर सुनने को मिलता था- आप तो भाग्यशाली हैं, स्वर्ग में रहते हैं। अब उदासी का रंग ओढ़े एक पंक्ति धार की तरह बरबस फूटती है- ....जी हां, हम स्वर्ग में रहते हैं, पर बरसात में स्वर्गवासी हो जाते हैं।

मंडी जिले के धर्मपुर में सौन खड्ड की गोद में बने बस अड्डे में बाढ़ से उत्पन्न दृश्य। जागरण

****

दैनिक जागरण

श्रद्धा भाव के बिना भक्ति का कोई अर्थ नहीं

विकास को गति देने का मंत्र

विकास सारस्वत

विनिर्माण में मध्यशक्ति बनने के लिए उद्यमियों को व्यापारी से उत्पादक बनाने के लिए प्रेरित करने के साथ श्रम एवं श्रमिकों के लिए सम्मान भी जगाना होगा

अमेरिका द्वारा बनाए जा रहे टैरिफ दबाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को तो रेखांकित किया ही, चीन से संबंधों को सामान्य बनाने का भी फैसला हुआ। इसी सिलसिले में इलेक्ट्रिक वाहन, रिन्यूएबल एनर्जी, टेबलटाइल मशीनरी, बिहुत एवं कृषि उपकरण, आटो पार्ट्स जैसे उद्योगों में चीनी निवेश को अनुमति दी गई है। पड़ोसी देश से रिश्तों में सुधार और विश्व की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देशों के बीच आर्थिक सहयोग का बढ़ना अच्छी बात है, परंतु चीन के साथ पहले से ही भारी व्यापार घाटा झेल रहे भारत के लिए चुनौती यह भी है कि वह अपने विनिर्माण क्षेत्र की गति दे।

दक्षिण-पूर्व एशिया के अभूतपूर्व औद्योगिक विकास और पश्चिमी देशों द्वारा उत्पादन क्षेत्र को पुनः बढ़ावा देने के प्रयासों से मुकाबला करने के लिए भारत को विनिर्माण को न सिर्फ गति देनी होगी, बल्कि इसमें गुणात्मक सुधार लाकर वैश्विक बाजार में अपना स्थान भी बनाना होगा। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत को पहले-पहल कुछेक क्षेत्र चयनित कर अपने लिए क्षेत्र-विशिष्ट उद्योगों की पहल करनी होगी और फिर धीरे-धीरे यथासंभव क्षेत्रों में विस्तार ही सकता है। ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत निराशाजनक स्थिति में हैं। सदी की शुरुआत तक भारत वैश्विक विनिर्माण पटल पर किसी गिनती में नहीं था। 2006 में हम विनिर्माण करने वाले शीर्ष दस देशों में आए और आज हम शीर्ष पांच देशों में से एक हैं। मोबाइल फोन निर्माण में दूसरा बड़ा उत्पादक बनने के बाद आज सेमीकंडक्टर युग में प्रवेश कर भारत ने उच्च प्रौद्योगिकी-गहन उद्योग में जगह बनाई है, परंतु 140 करोड़ आबादी वाले देश में हमें श्रम की खपत वाले उद्योगों की भी गंभीरता से लेना होगा। खासकर तब जब सबसे अधिक रोजगार सृजन इसी क्षेत्र से उत्पन्न होता है और भारत की अधिकांश अर्थकुशल श्रम शक्ति इसी क्षेत्र में खपाई जा सकती है।

पिछले दो दशकों से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 14 से 16 प्रतिशत के बीच अटकी हुई है। इसी दौरान चीन में यह हिस्सेदारी लगभग 30-35 प्रतिशत रही है। हाल के समय में सेवा क्षेत्र में आई बढ़त के कारण यह आंकड़ा घट कर 27 प्रतिशत पर आया है। यह कहना अनुचित होगा कि सरकारों ने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयास नहीं किए हैं। नीति निर्धारण स्तर पर कई सराहनीय पहल हुई हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना, बुनियादी ढांचा विकास के लिए एकीकृत और व्यापक पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान, उदार एफडीआइ नीति, निवेशकों की मंजूरी के लिए एक एकीकृत पोर्टल प्रदान करने के लिए नेशनल सिंगल विंडो स्कीम, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, कारपोरेट कर में कटौती आदि बहुत सी नीतियां और निर्णय विनिर्माण की गति देने के लिए गए हैं। बावजूद इसके कुछ ढांचागत एवं व्यावहारिक समस्याएं अब भी उद्योगों के लिए चुनौती बनी हुई हैं। ऐसी ही एक चुनौती उद्योगों के लिए भूमि की सीमित उपलब्धता है। उत्तर भारत में यह समस्या अधिक है। ऐसे में जहां कम कृषि पैदावार वाली भूमि को औद्योगिक उपयोग में लाने के प्रयास करने होंगे, वहीं चिह्नित भूमि का सर्वोत्तम उपयोग भी सुनिश्चित करना होगा। देखा गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत सी जमीन केवल निवेश और पुनर्विक्रय के लिए निष्क्रिय पड़ी है।

सरकार के काफी प्रयासों के बावजूद कौशल विकास की मुहिम कुछ खास कारगर नहीं हो पाई है। आवश्यकता है कि कौशल विकास का दायित्व निजी संस्थाओं के बजाय विश्वसनीय उद्योग निकायों को दिया जाए। स्वयं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अनुसार भारत में 2.9 करोड़ कुशल श्रमिकों की कमी है। अकेले सेमीकंडक्टर क्षेत्र में दो वर्षों में 15 लाख दक्ष कामगारों की आवश्यकता होगी। करीब 80 प्रतिशत रोजगार सृजन करने वाले छोटे एवं मझोले उद्योगों को ऋण पाने में आज भी कठिनाई होती है। विनिर्माण क्षेत्र में श्रम कानूनों को लेकर अनुकूल स्थिति नहीं है। जैसे 300 से ज्यादा कर्मियों वाले उद्योगों में छंटनी मुश्किल है, जबकि सेवा क्षेत्र में यह नीति लचीली है। इसके अलावा कमजोर ब्रांडिंग, अनुसीधन और नवीनीकरण में हिचकिचाहट, अनुसीधन और नवीनीकरण में हिचकिचाहट, अनुसीधन और नवीनीकरण में दिलाई, पेशेवर दृष्टिकोण की कमी जैसी कुछ समस्याएं हैं, जिन्हें उद्योग जगत ने खुद खड़ा किया है। नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को दिया गया महत्व इस दिशा में सराहनीय है, परंतु अभिभावकों की मानसिकता में बदलाव से ही अपेक्षित परिणाम निकल पाएंगे।

समाज के सबसे अच्छे मानव संसाधन का अधिकांश हिस्सा उद्यमशील न होकर नौकरियों की ओर भाग रहा है। हमारे सामाजिक सोच में ऐसा बदलाव आया है जो प्रतिभावान और प्रतिभाहीन दोनों ही वर्गों को कल कारखानों से विरत कर कुर्सी-मेज वाली जीविका की ओर भाग रहा है। एक राष्ट्र के तौर पर अनुशासन और निष्ठा की कमी भी उद्यमशीलता को प्रभावित कर रही है। आवश्यकता इसकी है कि उद्यमियों को व्यापारी से उत्पादक बनाने के लिए प्रेरित किया जाए और श्रम एवं श्रमिकों के लिए समाज में सम्मान जगाया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भ्रष्टाचार को सहन करके कोई भी देश उद्यमी या विकसित नहीं हो पाया है। सरकारी लालफीताशाही और भ्रष्टाचार उद्यमशील भारत के रास्ते में बड़ी बाधा हैं। नियमों के अनुपालन को सरल और न्यूनतम बनाने के अलावा नौकरशाही को समन्वयक के रोल में लाना होगा। उद्योग से संबंधित विभागों में नौकरशाही की संख्या इससे तय करना होगी कि वह कितने नए उद्योग लगवाने में सफल रहे, कितने उद्योगों का विस्तार हुआ और उन उद्योगों में कितने ऐसे उद्योग थे जो आयात पर निर्भरता को कम करते हैं या निर्यात को बढ़ावा देते हैं। युवा जनसांख्यिकी, बढ़ता मध्यम वर्ग, तेजी से विकसित होता बुनियादी ढांचा ऐसे कुछ कारण हैं जिनके चलते विनिर्माण में भारत का भविष्य संभावनाओं से भरा हुआ है। आवश्यकता केवल इतनी है कि तात्कालिक लक्ष्यों से परे एक दूरगामी नीति के तहत विनिर्माण को राष्ट्रीय मिशन बनाकर कार्य किया जाए।

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

कानूनों का दुरुपयोग

दहेज उत्पीड़न के एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की, वह यही बताती है कि दहेज रोधी कानून का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। यह पहली बार नहीं है जब किसी उच्चतर अदालत ने इस कानून के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई हो अथवा अपनी टिप्पणी से देश का ध्यान आकर्षित किया हो। दिल्ली हाई कोर्ट की तरह से अन्य उच्च न्यायालय भी इस तरह की टिप्पणियां कर चुके हैं। और तो और कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी ही टिप्पणियां कर चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने समक्ष उपस्थित मामले की सुनवाई करते हुए न केवल दहेज उत्पीड़न की झूठी प्राथमिकी रद करने का आदेश दिया, बल्कि इस आवश्यकता पर भी बल दिया कि दहेज उत्पीड़न के झूठे मामलों में फंसे लोगों को उत्पीड़न से बचाना अदालत का कर्तव्य है। क्या यह उम्मीद की जाए कि उसकी टिप्पणी का सभी अदालतें संज्ञान लेंगी और दहेज निवारण अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए सक्रियता दिखाएंगी? उन्हें ऐसा करना ही होगा, क्योंकि कुछ मामले ऐसे आए हैं, जिनमें दहेज के झूठे मामले में फंसे लोगों ने आत्महत्या कर ली।

केवल दहेज निरोधक कानून का ही दुरुपयोग नहीं हो रहा है। इसके साथ ही कुछ अन्य कानूनों का भी दुरुपयोग हो रहा है। इनमें कई कानून ऐसे हैं, जो महिलाओं को उत्पीड़न-शोषण से बचाने के लिए बनाए गए हैं। दहेज निरोधक कानून के अलावा जिस कानून का दुरुपयोग आम हो चला है, वह है दुष्कर्म रोधी कानून। दुष्कर्म के झूठे मामले सामने आने का जो सिलसिला कायम है, वह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस कानून के दुरुपयोग पर भी अदालतों की ओर से कठोर टिप्पणियां की जा चुकी हैं। कुछ मामले तो ऐसे भी रहे हैं, जिनमें दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाने वाली महिलाओं को सजा भी सुनाई गई। निःसंदेह दुष्कर्म और दहेज के झूठे मामलों के आधार पर ऐसे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि महिलाओं को दहेज के लिए तंग नहीं किया जाता अथवा वे दुष्कर्म का शिकार नहीं होतीं। सच तो यह है कि ऐसी घटनाएं थी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इन स्थितियों में उन उपायों पर विचार करने की जरूरत है, जिनसे किसी भी कानून के मनमाने इस्तेमाल को रोका जा सके। वैसे तो दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं, जिसका दुरुपयोग न होता हो, लेकिन जिन कानूनों का दुरुपयोग बढ़ता चला जा रहा है और जो उत्पीड़न एवं उगाही का जरिया बन गए हैं, उनमें ऐसे कुछ संशोधन-परिवर्तन करने पर विचार होना चाहिए, जिससे उनके बेजा इस्तेमाल को रोका जा सके। ऐसा करते समय इस पर ध्यान देना होगा कि महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाए गए अनेक कानून लिंग निरपेक्ष नहीं हैं और इसीलिए उनका दुरुपयोग बढ़ गया है।

आपदा की मार

उत्तराखंड में वर्षा और भूस्खलन का कहर जिंदगी पर भारी है। पिछले डेढ़ महीने से आपदाओं ने जन जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। मूलभूत सुविधाएं ध्वस्त हैं। पहाड़ को लाइफलाइन कही जाने वाली सड़कें खस्ताहाल हैं। नदी-नालों का उफान दिन का चैन और रात की नींद उड़ाए हुए है। उच्च हिमालय से लेकर मैदान तक तबाही के निशान गहरे होते जा रहे हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी और बागेश्वर के बाद अब देहरादून में अतिवृष्टि ने भारी नुकसान पहुंचाया है। देहरादून की कई कालोनियां खतरे की जद में हैं तो भूस्खलन व पुल क्षतिग्रस्त होने से पांवटा व मसूरी मार्ग अवरुद्ध हैं। आपदा से देहरादून बेहाल है। राज्य गठन के बाद देहरादून को अस्थायी राजधानी का ताज मिला और यहीं से शहर के चारों ओर फैली हरियाली को अनियंत्रित विकास ने निगलना शुरू किया। देहरादून से मसूरी, सहस्रधारा, हरिद्वार, ऋषिकेश, पांवटा जाने वाली सड़कों के दोनों छोर कंक्रीट के जंगल में बदल गए। नदी, नालों व खालों के किनारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की कतार लग गई। नियमों को ताक पर रखकर निर्माण हुए। ऐसा नहीं है कि अनियोजित विकास को लेकर चिंता नहीं दिखाई दी, लेकिन इसका हल नहीं खोजा जा सका। राज्य गठन के बाद दून के प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। राजधानी होने की आवश्यकताओं की पूर्ति में दून शहर हांफ रहा है। भविष्य के लिए यह प्रकृति का संदेश भी है कि सीमाओं का अतिक्रमण होगा तो उसका नुकसान होना तय है। ऐसे में नीति निर्धारकों को अधिक सतर्क व सजग होना होगा।

आपदा के लिए हम भी जिम्मेदार हैं। गलतियां सुधारकर भविष्य में अनियोजित विकास पर हर हाल में अंकुश लगाना होगा

वैचारिक भटकाव के शिकार आइआइटी

अपने उत्कृष्ट तकनीकी संस्थानों की श्रेष्ठता के लिए उनकी मौलिक धारा को बनाए रखना होगा

संक्रांत सानु

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर रहेछात्रों का पूरा ध्यान। फाइल

आइआइटी के जिन परिसरों में प्रयोगशालाएं, तकनीक, विज्ञान की गूंज होनी चाहिए, वहां अब विरोध, धरना और राजनीतिक नारे सुनाई देने लगे हैं। उसके इस वैचारिक भटकाव का उदाहरण बकोले में एक सम्मेलन का आइआइटी-बांबे का सह-प्रायोजक बनना रहा। सठठ फ़शियन कैपिटलिज्म नामक यह आयोजन इंस्टीट्यूट फार सठठ एशिया स्टडीज और यूनिवर्सिटी आफ मैसाचुसेट्स-एमहर्स्ट द्वारा किया गया। यह आयोजन भारतीय उद्योग और उद्यमिता को शोषण की व्यवस्था बताता था। विरोध में आवाज उठने पर आइआइटी बांबे को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा कि उसका इस आयोजन से कोई लेना-देना नहीं। यह ध्यान रखा जाए कि आइआइटी की स्थापना का उद्देश्य विशिष्ट तकनीकी संस्थानों की रचना था, जहां से विज्ञानी, अभियंता और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ निकलकर भारत को आत्मनिर्भर बना सकें। प्रयोगशाला-आधारित शिक्षा, उपयुक्त अनुसंधान और पूर्व छात्रों का वैश्विक नेटवर्क ही आइआइटी को वास्तविक पहचान रहा है। इसी ध्येय ने उन्हें भारत के अन्य विश्वविद्यालयों से अलग और विशिष्ट बनाया, किंतु यूपीए शासनकाल में यह ध्येय विचलित होने लगा।

यशपाल समिति ने 2008-09 में अनुसंधा की कि आइआइटी और आइआइएम को बहुविषयी विश्वविद्यालय बनाया जाए। यह योजना सतही रूप में आकर्षक प्रतीत होती थी, किंतु यह मार्गभ्रष्ट करने वाली थी। तकनीकी उत्कृष्टता के लिए निर्मित संस्थान को सामान्य विश्वविद्यालय का रूप देने का अर्थ था उसकी विशिष्ट पहचान का ह्रास। आइआइटी में मानविकी विषयों का प्रसार संस्थान की प्रतिष्ठा में कोई नवीन मूल्य नहीं जोड़ सका है। इसके विपरीत, इसने उनकी स्थापित ख्याति का सहारा लेकर परिसर को राजनीतिक आंदोलनों और विचारधारात्मक टकरावों का मंच बना दिया है। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए कुछ मानविकी विषयों का परिचय निश्चय ही हितकर है, लेकिन अब आइआइटी मानविकी विषयों में पूर्ण स्नातकोत्तर और शोध कार्यक्रम चला रहे हैं। आइआइटी-मद्रास ने 2006 में पंचवर्षीय एमए प्रारंभ किया, जिसे बाद में द्विवर्षीय पाठ्यक्रमों-अर्थशास्त्र, अंग्रेजी और विकास-अध्ययन-में विभक्त किया गया। आइआइटी-गांधीनगर ने 2014-15 में 'समाज एवं संस्कृति' में एमए प्रारंभ किया। आइआइटी-बांबे और आइआइटी-दिल्ली अब अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, साहित्य तथा मनोविज्ञान में पीएचडी तक प्रदान कर रहे हैं। यह आइआइटी के उद्देश्य से उलट है। जहां अभिभावकों को व्यापक दृष्टिकोण देना था, वहां अब सामान्य विश्वविद्यालय जैसी समानांतर मानविकी शिक्षा स्थापित हो रही है।

मानविकी की वजह से परिसर में प्रायः राजनीति स्वतः प्रवेश कर जाती है। आइआइटी-मद्रास का अंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्किल 2015 से विवादों में है। आइआइटी-बांबे में नागरिकता संशोधन कानून पर विरोध-आंदोलन हुए। आइआइटी कानपुर में छात्रों ने जामिया, एएमयू के समर्थन में जुलूस निकाला और फैज की कविता 'हम देखेंगे' पढ़ी। उस कविता को लेकर 'सांप्रदायिक' होने का आरोप लगा और आंतरिक जांच समिति गठित करनी पड़ी। ये दूरय उन सामान्य विश्वविद्यालयों के प्रतीत होते हैं जहां वर्षों से राजनीति का वर्चस्व रहा है, किंतु आइआइटी जैसे तकनीकी संस्थानों के लिए यह अस्वाभाविक और हानिकारक है।

आइआइटी-दिल्ली के मानविकी विभाग की एक सहयोगी प्राध्यापिका ने 2023 में हिंदू धर्म को 'प्रपंच' करार दिया। ऐसे कथन आइआइटी की प्रतिष्ठा का उपयोग कर वैचारिक कलह फैलाते हैं, जबकि उनका संस्थान की तकनीकी पहचान से कोई संबंध नहीं है। आइआइटी का नाम इस प्रकार राजनीतिक और विचारधारात्मक युद्धभूमि बनाने के लिए प्रयुक्त होना संस्थान और राष्ट्र, दोनों के लिए घातक है। आइआइटी को 'सामान्य विश्वविद्यालय' बनाने का नुकसान यह है कि मानविकी विषयों का फैलाव महंगे विज्ञान और तकनीकी विषयों पर बोझ डालता है। मानविकी के लिए पहले से ही भारत में पर्याप्त विश्वविद्यालय हैं, किंतु अभाव है तो तकनीकी विशेषज्ञों और नवाचार-आधारभूत संरचनाओं का। यदि संसाधन सीमित हैं तो उनका प्रयोग वहीं होना चाहिए, जहां उनका अधिकतम राष्ट्रीय लाभ हो। यह सच है कि भारत की दोनों प्रकार की संस्थाएं चाहिए-सामान्य बहुविषयी विश्वविद्यालय और विशिष्ट तकनीकी संस्थान, किंतु यदि तकनीकी संस्थानों की ही सामान्य बना दिया जाएगा तो हम अपनी विशेषता खो देंगे। अब समय है कि हम आइआइटी को उनके मौलिक मार्ग पर पुनःस्थापित करें। विधि में संशोधन कर यह सुनिश्चित करना होगा कि आइआइटी तकनीकी विश्वविद्यालय ही बने रहें। मानविकी विषय केवल स्नातक स्तर की पूरक शिक्षा तक सीमित हों। राजनीतिक गतिविधियों को परिसरों से दूर रखा जाए, ताकि कक्षाएं और प्रयोगशालाएं पुनः नवाचार का केंद्र बन सकें। पूर्व छात्रों को भी अपना योगदान प्रयोगशालाओं, अनुसंधान-केंद्रों और तकनीकी छात्रवृत्तियों में लगाना चाहिए। जब चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), चिप-डिजाइन और क्वांटम कंप्यूटर में तीव्र गति से प्रगति कर रहा है, तब भारत अपने श्रेष्ठतम संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा बनाने की भूल नहीं कर सकता। आइआइटी को तकनीकी उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में सुरक्षित रखना ही होगा। यही समय है स्पष्ट शब्दों में कहने का-आइआइटी हमें पुनः चाहिए।

(लेखक आइआइटी के स्नातक और गरुड़ प्रकाशन के संस्थापक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

विनयशीलता

विनय का गुण व्यक्तित्व की आभा को बढ़ाता है। विनयशील व्यक्ति लोकप्रिय होता है। सभी उससे स्नेह रखते हैं। विनयशीलता ही सहृदयता को जन्म देती है। स्नेहदयी श्रद्धावान एवं परोपकारी होता है। जीवन में उच्च आदर्श स्थापित करने वाले लोगों में विनयशीलता का गुण कूट-कूट कर भरा होता है। ऐसे लोगों का जीवन अनुकरणीय बन जाता है। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके सत्संगों से ही आलोकित होता है। आज के समय में व्यक्ति विलासिता का दास बनकर अहंकार की टोकरी सिर पर ढो रहा है। उसके भीतर 'मैं' ही सर्वोत्तम का भाव पलने लगा है। ऐसे समय में विनयशीलता और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। विनय भाव से ओतप्रोत व्यक्ति के सामने अहंकार फटक भी नहीं पाता। वह सदैव विनम्रता की साधना में लीन रहता है। विनम्रता से ही पात्रता की स्थिति निर्मित होती है।

इस संदर्भ में एक कथा बड़ी रोचक है। एक राजा चांडाल से ब्रह्म विद्या सीखने की इच्छा रखता है। वह उसे दरबार में बुलाता है। राजा अपने सिंहासन पर बैठा रहता है और चांडाल उसके चरणों में बैठकर उसे मंत्र और विधान बताता है, किंतु बहुत प्रयासों के बाद भी राजा विद्या नहीं सीख पाता। राजा बड़ा चिंतित हो जाता है। तब राजा का एक विद्वान मंत्री उन्हें समझाता है कि 'विद्या सदैव विनयशीलता से प्राप्त होती है, अहंकार से नहीं। गुरु का स्थान सदैव सीखने वाले से उच्च होता है। आपको चांडाल से विद्या सीखने के लिए अपना आसन उससे नीचे लगाना होगा।' मंत्री की बात सुनकर राजा ऐसा ही करता है और वह कुछ ही दिनों में उस विद्या को सीख लेता है। यही विनयशीलता की सामर्थ्य है।

हमें भी अपने जीवन में विनयशीलता के गुण को अंगीकार कर आगे बढ़ने के प्रयास करने चाहिए। विनय भाव हमें सदैव सकारात्मक बनाता है। विनयशीलता की आधारशिला पर ही एक अनुकरणीय व्यक्तित्व आकार ले पाता है।

ललित शैर्य

वनतारा : संरक्षण और पारदर्शिता की जीत

अमन सिंह गौर

वनतारा मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने पशुओं के संरक्षण को एक नई दिशा दी है

भारत जैसे देश में जहां वन्यजीव संरक्षण केवल पर्यावरणीय जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक विरासत का भी हिस्सा है, वहां किसी भी बड़े प्रयास पर सवाल उठना स्वाभाविक है। गुजरात के जामनगर जिले में स्थित वनतारा केंद्र भी इसी कसौटी से गुजरा। घायल और लुप्तप्राय प्रजातियों को सुरक्षित आश्रय देने की इस पहल पर जब तस्करी, अवैध अधिग्रहण और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगे तो यह बहस केवल एक संस्थान तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे संरक्षण तंत्र की विश्वसनीयता का सवाल बन गई। लेकिन इस मामले में अच्छी बात यह रही कि इन संदेहों को न तो दबाया गया और न अनदेखा किया गया।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक हित याचिकाओं के आधार पर विशेष जांच दल का गठन किया और महीनों तक चलने वाली विस्तृत पड़ताल करवाई। जांच में न केवल वनतारा की सुविधाओं का निरीक्षण हुआ, बल्कि दस्तावेजों, अनुमति-पत्रों और वित्तीय लेनदेन का भी सूक्ष्म विश्लेषण किया गया। निष्कर्ष स्पष्ट थे। वनतारा ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के दिशा-निर्देश और अंतरराष्ट्रीय संधियों का पालन किया। जानवरों का अधिग्रहण और स्थानांतरण नियम सम्मत पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने संस्था को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया और यह भी निर्देश दिया कि इन्हीं आरोपों पर आधारित कोई नई याचिका अब स्वीकार नहीं की जाएगी।

यह निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पहला कारण यह कि इससे स्पष्ट हुआ कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में किसी भी संस्था, चाहे वह कितनी ही प्रभावशाली क्यों न हो, उसे कानून की कसौटी से गुजरना ही होगा। दूसरा यह विश्वास भी मजबूत हुआ कि संस्थागत पारदर्शिता अंततः अविश्वास की परतों को हटा देती है। यदि शुरुआत से ही पारदर्शिता और संवाद का स्तर ऊंचा होता तो शायद विवाद खड़ा ही न होता।

यह समझना होगा कि संरक्षण केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सहभागिता की भी है। स्थानीय समुदाय और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सख्त लिए बिना किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए विश्वास कायम करना कठिन है। कारपोरेट भागीदारी को लेकर भी यही सबक सामने आया है। सरकार अकेले वन्यजीव संरक्षण का दायित्व नहीं निभा सकती। निजी क्षेत्र की भागीदारी स्वागतयोग्य है, बशर्ते उसमें जवाबदेही और स्वतंत्र निगरानी की जगह बनी रहे। वनतारा को मिली कानूनी छूट इस तथ्य को नकारती नहीं कि जनता का विश्वास ही उसकी असली पूंजी है। इस प्रकरण से निकला बड़ा संदेश यह है कि पारदर्शिता और संस्थागत प्रक्रिया ही संरक्षण प्रयासों को टिकाऊ बना सकती है। अदालत का निर्णय वनतारा के लिए राहत है, किंतु यह अन्य सभी संस्थाओं के लिए चेतावनी भी है कि संरक्षण के नाम पर संदेह से बचने का एकमात्र उपाय ईमानदार संवाद और कठोर जवाबदेही है।

(लेखक वीएनयू में शोधार्थी हैं)

रोका जाए मतांतरण का सिलसिला

'मतांतरण रोधी कानून' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में एक वास्तविक चिंता को समग्रता के साथ रेखांकित किया गया है। यह बहुत गलत है कि कुछ लोग छल-छद्म से मतांतरण के खेल में लगे हैं और इसके लिए वे गरीबों, वंचितों और आदिवासी लोगों को शिकार बना रहे हैं। यह किस धर्म-पंथ-मजहब में लिखा है कि आस्था के नाम पर छल करना, दूसरों को गुमराह करना? अगर ये लोग गरीबों या अन्य लोगों का कोई भला करना ही चाहते हैं, उनकी किसी तरह की कोई मदद करना चाहते हैं, तो वे मतांतरण के लिए मजबूर ही क्यों करते हैं? क्यों, जो लोग लोभ में आकर मतांतरण करते हैं, वे यह सिद्ध कर देते हैं कि उन्हें धर्म से नहीं भौतिकतावाद से प्यार है। हालांकि जिस धर्म के लोगों को मतांतरण के लिए निशाना बनाया जा रहा है उसके जिम्मेदार लोगों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे उन कारणों की पड़ताल करें, जिसके चलते ऐसा हो रहा है और उसके आवश्यक निवारण भी करें। मतांतरण का यह कुचक्र देश का माहौल बिगाड़ रहा है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

समाज विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण

बुधवार को प्रकाशित अग्रलेख 'मतांतरण रोधी कानून' में मतांतरण रोकने के लिए लागू राज्यों के कानूनों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका और चुनौती पर बेबाकी से राय व्यक्त की गई है। याचिकाकर्ताओं ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के हनन को आधार बनाकर राज्यों द्वारा पारित कानूनों को रद करने की वकालत की है। धर्म परिवर्तन की समस्या का मूल धार्मिक कट्टरता है, जिसमें अन्य धर्मों के अनुयायियों को मतांतरण हेतु बाध्य करने के लिए लोभ-लालच दिया जाता है या भय दिखाया जाता है। ऐसा करने वाले अन्य धर्मों को निकृष्ट और केवल स्वयं के धर्म को सर्वोत्तम मानते हैं। मतांतरण करने हेतु लव जिहाद का शिगूफा चलाया जा रहा है। लव जिहाद में अपनी पहचान छुपाकर अन्य धर्मों की युवतियों को फंसाया जाता है और फिर उन्हें मतांतरण हेतु बाध्य किया जाता है। इसे रोकने के लिए राज्यों ने सख्त कानून बनाए, परंतु ऐसा कर रहे लोग इसके विरोध में उतर गए हैं और कानून की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। सवाल यह है कि धोखे, दबाव और छल से किए गए धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए वे स्वयं क्या कर रहे हैं? यदि कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो यह कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन यदि कोई अन्य व्यक्ति को फुसलाकर, डराकर, धोखे में रखकर या मजबूर करके धर्म परिवर्तन कराता है तो यह कानूनन अपराध है, लिहाजा ऐसे मामलों पर अंकुश लगना चाहिए।

मोहित सोनी, कुक्षी, मध्य प्रदेश

पीएम मोदी के नेतृत्व की कुशलता

संपादकीय आलेख 'सशक्त भारत के शिल्पकार मोदी' में अमित शाह ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जन्मतिथि के रूप में एक महत्वपूर्ण दिवस को रेखांकित किया है। 142 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए 75 वर्ष की उम्र में भी जिस उत्साह से देश को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, वह अपने आप में मिसाल प्रस्तुत करता है। निसंदेह उनके कार्यकाल में अनेक ऐसे कार्य हुए हैं जो आजादी के वर्षों बाद तक न केवल जनाकांक्षाओं के आकलन के उपेक्षित थे, बल्कि देश के पिछड़ेपन के बहाने बने हुए थे। मोदी के कार्यकाल में लिए गए निर्णयों ने न केवल देश के बहुसंख्य गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया, बल्कि वैश्विक पटल पर देश को उच्चतम शिखर पर पहुंचाया। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि ने बुनियादी स्तर पर राष्ट्र को सुदृढ़ किया है। अनुच्छेद 370 का मसला, तीन तलाक का मसला ऐसे कुछ निर्णय रहे जो वर्षों से असंभव से लग रहे थे। पीएम मोदी के कार्यकाल में आपरेशन सिंदूर एक ऐसा अभियान है जिसने साबित कर दिया कि बुद्ध का देश युद्ध का हिमायती नहीं रहा है, पर आतंकवादी दुस्साहस को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मिथिलेश कुमार, भागलपुर, बिहार

मेलबाक्स

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संरक्षक: स्व. पूर्णचंद गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक: स्व. नरेंद्र मोहन, पूर्व एक्जीक्यूटिव चेयरमैन: महेंद्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक: संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीलेन्द्र बीजल्वल द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और डाबी के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक: (राष्ट्रीय संस्करण) -विनय प्रकाश त्रिपाठी *

डाटा वैज्ञानिकों की बढ़ती जरूरत

व्यवसाय विशेषज्ञों पर अब भारी पड़ने लगे हैं डाटा वैज्ञानिक या डाटा विशेषज्ञ। तमाम कंपनियां अपने खर्च, व्यय, अनुभव के डाटा के आधार पर सही निर्णय लेने के लिए प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का सहारा लेने लगी हैं। वित्त से लेकर सप्लाई चेन तक, सभी उद्योगों में इस कौशल की मांग बढ़ रही है। इस क्षेत्र में कैसे बन रही है करियर की राह, बता रहे हैं निशित पाठक

वर्तमान में डाटा सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। वैश्विक स्तर पर एआई के बढ़ते कदम दरअसल डाटा की नींव पर ही जमे हुए हैं। डाटा एनालिटिक्स इसीलिए लगभग हरेक उद्योग की जरूरत है, जिसमें अब पूर्वानुमान करने वाली प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स पर कंपनियां जोर दे रही हैं। इसे भविष्य का कौशल माना जा रहा है।

प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का वैश्विक बाजार वर्तमान में करीब 2 लाख करोड़ रुपये है, जो 2030 तक 7 लाख करोड़ से आगे जाने की उम्मीद है। वहीं, भारत में डिजिटल इंडिया, एआई मिशन और तेजी से बढ़ती डाटा इकोनॉमी ने इसे मजबूती दी है। देश में 2025 के अंत तक इसका बाजार 9000 करोड़ और 2033 तक 55,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। हर साल 20 से 25 फीसदी की दर से बढ़ता यह क्षेत्र करियर के लिए तेजी से उभरता विकल्प बन गया है।

क्या है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स

यह तकनीक पुराने डाटा और पैटर्न का विश्लेषण कर भविष्य की संभावनाओं का अनुमान लगाती है। उदाहरण के लिए बैंक धोखाधड़ी वाले लेन-देन की पहचान कर सकते हैं या हेल्थकेयर में मरीजों की गंभीर स्थिति का पूर्वानुमान कर इलाज की सही तैयारी हो सकती है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स टेक्नोजुएट्स, डाटा पेशेवरों के लिए बहुत काम का कौशल साबित हो सकता है।

डाटा एनालिटिक्स से अलग कैसे : डाटा एनालिटिक्स का उद्देश्य मौजूदा डाटा का विश्लेषण कर यह समझना है कि क्या हुआ और क्यों हुआ? इसमें ऐसे टूल्स का उपयोग होता है, जो डाटा को साफ, व्यवस्थित और विजुअलाइज करने में मदद करते हैं। वहीं, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने पर केंद्रित है, जिसमें मशीन लर्निंग और एआई आधारित टूल्स की जानकारी जरूरी है।

कैसे होगा काम

प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में नौकरी की तैयारी करें, तो पायथन और उसकी लाइब्रेरीज जैसे **Scikit-learn** पर मजबूत पकड़ बनाना जरूरी है। टैब्लू और पावर बीआई जैसे विजुअलाइजेशन टूल्स का ज्ञान आपको एक मजबूत उम्मीदवार बनाएगा।

प्रारंभिक स्तर पर काम : मुख्य तौर पर डाटा क्लीनिंग, रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड बनाना होता है।

योग्यता : मैथ्स/स्टैटिस्टिक्स / कंप्यूटर साइंस (सीएस) में बीएससी या आईटी/ सीएस में बीटेक डिग्री आवश्यक होती है। एक्सेल, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, पायथन या आर की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए।

मध्यम स्तर पर काम: इस स्तर की जॉब्स के लिए मशीन लर्निंग मॉडल बनाना और जटिल डाटा से पूर्वानुमान या आकलन करना शामिल है।

योग्यता : इस स्तर पर एमएससी, डाटा साइंस या बिजनेस एनालिटिक्स में एमबीए जैसे कोर्स लाभकारी होते हैं।

उच्च स्तर पर: टीम नेतृत्व, स्ट्रैटेजी निर्माण और संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने जैसी जिम्मेदारियों के पद पर नियुक्ति मिलेगी।

आवश्यक योग्यता : इस स्तर पर आमतौर पर पीएचडी धारक या संबंधित क्षेत्र में लंबे अनुभव वाले पेशेवर चुने जाते हैं, जो हेल्थकेयर, फाइनेंस या एनर्जी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं।

किन पदों पर मौके

एंट्री लेवल में डाटा एनालिस्ट, जूनियर बिजनेस एनालिस्ट, रिपोर्टिंग एनालिस्ट जैसी भूमिकाएं मिलती हैं। कार्य अनुभव के आधार पर बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, प्रिडिक्टिव मॉडल, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कंसल्टेंट, एआई/एमएल सॉफ्टवेयर, चीफ डाटा ऑफिसर जैसे पदों पर अच्छी संभावनाएं मिलेंगी।

अपस्किलिंग के लिए

- इंटीग्रेडक्शन टू डाटा एनालिटिक्स (कोर्सेरा)
- एक्सेल फॉर डाटा एनालिसिस (उडेमी)
- प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर बिजनेस (उडेसिटी)
- आईआईएमबी एक्स : प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स (एडाप्क्स/स्वयं)
- एनआईआईटी और एपटेक जैसे संस्थानों से डाटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, एसक्यूएल और एक्सेल जैसे कोर्स किए जा सकते हैं। यहां प्रमाणित ट्रेनर्स से सीखने, व्यावहारिक अनुभव देने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है, जो आपके रिज्यूमे और करियर दोनों को मजबूत बनाता है। डाटा एनालिटिक्स के कूट कैंप करें।

विशेषज्ञों की राय

कंपनियां ऐसे पेशेवरों को प्राथमिकता देती हैं, जो डाटा से भविष्य के ट्रेंड समझकर व्यावहारिक समाधान दे सकें। नियुक्तियों में उन्हें वरीयता मिलती है, जिनके पास पायथन, एआई/ एमएल जैसे तकनीकी दक्षता, डोमेन ज्ञान और बेहतर संचार कौशल हो। छात्रों को डाटा के आधार पर दिशा तय करना सीखना होगा। यह कौशल ही प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में करियर को अलग पहचान दिलाता है।

निमिष चतुर्वेदी, मैनेजिंग डायरेक्टर, कैलाशा सेतु प्राइवेट लिमिटेड

प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स आने वाले वर्षों में हेल्थकेयर में बड़ा बदलाव लाएगा। यह मरीज-केंद्रित इलाज व संसाधनों के बेहतर उपयोग को संभव बनाता है। इसीलिए डाटा साइंटिस्ट एवं हेल्थकेयर एनालिटिक्स की मांग बढ़ रही है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हेल्थकेयर और डाटा एनालिटिक्स की समझ विकसित करें, क्योंकि जमीनी चुनौतियों से जुड़ने वाले पेशेवरों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी।

– फराज मिर्जा, हेल्थ केयर मार्केटिंग और ऑपरेशन विशेषज्ञ

अनुमानित वेतन :

पद के अनुसार प्रारंभिक वेतन लगभग 5 लाख रुपये सालाना हो सकता है, जो अनुभव और योग्यता के साथ 10 लाख या उससे अधिक हो सकता है।

डाटा एनालिटिक्स से प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की ओर : अगर कोई पेशेवर डाटा एनालिटिक्स से प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में जाना चाहता है, तो उसे मशीन लर्निंग, पायथन और स्टैटिस्टिक्स की बुनियादी समझ लेनी होगी। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर काम कर मॉडल बनाना, उनका विश्लेषण करना और डोमेन की समस्याएं हल करना जरूरी है। अपने प्रोजेक्ट्स गिटहब या पोर्टफोलियो में जोड़ें। मौजूदा काम में प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के छोटे प्रयोग शुरू करें। गूगल, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट जैसे मंच से कोर्स और सर्टिफिकेशन लेकर स्किल्स मजबूत करें।

जॉब/करियर

- बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। दसवीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

कुल पद : 3727
अंतिम तिथि: 26 सितंबर 2025
आवेदन प्रक्रिया : दिए गए वेबसाइट **bssc.bihar.gov.in** पर जाएं।

- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अप्रेंटिस की रिक्तियां निकली हैं।

कुल पद : 523
अंतिम तिथि: 11 अक्तूबर 2025
आवेदन प्रक्रिया : आधिकारिक वेबसाइट **iocl.com** पर जाना होगा।

- महानिदेशालय, सीमा सुरक्षा बल ने कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर एवं रेडियो मेकेनिक) के पदों पर आवेदन मांगे हैं।

कुल पद : 1121
अंतिम तिथि: 23 सितंबर 2025
आवेदन प्रक्रिया : आधिकारिक वेबसाइट **bsf.gov.in** पर लॉगइन करें।

- एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एक्जीक्यूटिव के विभिन्न पदों पर भर्ती है।

कुल पद : 976
अंतिम तिथि: 27 सितंबर 2025
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट **aai.aero** पर लॉगइन करें।

- दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट सहित अन्य पदों पर आवेदन मांगे गए हैं।

कुल पद : 334
अंतिम तिथि: 24 सितंबर 2025
आवेदन प्रक्रिया : आधिकारिक वेबसाइट **dsssb.delhi.gov.in** पर जाएं।

- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

कुल पद : 122
अंतिम तिथि: 02 अक्तूबर 2025
आवेदन प्रक्रिया : बैंक की आधिकारिक वेबसाइट **sbi.bank.in** पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

- बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से विभागाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

कुल पद : 218
अंतिम तिथि: 30 सितंबर 2025
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन भरना होगा। वेबसाइट है- **bpsc.bihar.gov.in**

- रेलवे भर्ती सेल, पश्चिम मध्य रेल में अप्रेंटिस की भर्तियां की जाएंगी।

कुल पद : 2865
अंतिम तिथि: 29 सितंबर 2025
आवेदन प्रक्रिया : दिए गए वेबसाइट **wcr.indianrailways.gov.in** पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

(**नोट :** आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट से अपने स्तर पर जांच कर लें।)

भेजें अपना सवाल

करियर या शैक्षिक कोर्स संबंधी आपके मन में कोई उत्कंठा है या कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपने सवाल नीचे दी गई ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ उसके जवाब देंगे। इस ईमेल आईडी का उपयोग करें **nayiraheincareer@gmail.com**

बारहवीं के बाद अच्छे सरकारी मौके

एक्सपर्ट टिप्स
आशीष आदर्श
करिअर काउंसलर

मैं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हूं और अभी 10+2 की पढ़ाई कर रही हूं। आगे पढ़ाई कर पाने में असमर्थ हूं। क्या 10+2 के बाद सरकारी नौकरी लग सकती है ?
रुक्मिणी सिंह

सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बारहवीं के बाद एसएससी यानी स्टाफ सेलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम एक अच्छा करियर विकल्प है। विभिन्न मंत्रालयों व सरकारी विभागों में ग्रुप सी और ग्रुप डी स्तर की नौकरियों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत एलडीसी यानी लोअर डिविजनल क्लर्क, जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटेरियेट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पद शामिल हैं। किसी भी विषय से 10+2 और 18 से 27 वर्ष तक की आयु सीमा के युवा इस पद के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

परीक्षा के मुख्यतः तीन चरण हैं : टियर 1- कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, अंग्रेजी और सामान्य गणित के प्रश्न शामिल होते हैं, वहीं टियर-2 के अंतर्गत निबंध लेखन और टियर -3 के अंतर्गत टाइपिंग टेस्ट में बैठना होता है। इस परीक्षा के लिए कमीशन द्वारा अप्रैल माह में विज्ञापन निकाला जाता है, जिसके बाद जून-जुलाई में परीक्षा आयोजित की जाती है। विस्तृत जानकारी के लिए कमीशन की वेबसाइट **ssc.nic.in** देखें।

■ मैं हिंदी से स्नातक हूं। आगे बीएसएफ या एनएसजी जैसे संगठन में अधिकारी के रूप में सेवा देना चाहता हूं। मार्गदर्शन करें।
राजेश कुमार

भारत सरकार के अंतर्गत कई ऐसी एजेंसियां हैं, जिनके काम में विभिन्न सीमाओं पर देश की रक्षा करना, एअरपोर्ट सहित विभिन्न सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, चुनावों विभिन्न आपात स्थिति में कानून व्यवस्था बहाल करना इत्यादि शामिल हैं। इसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सर्विस सेलेक्शन बोर्ड) या असम राइफल्स शामिल हैं। किसी भी विषय से ग्रेजुएट हैं और अधिकतम आयु 25 वर्ष है, तो उपरोक्त एजेंसियों में असिस्टेंट कमांडर के पद पर नियुक्ति हेतु यूपीएससी द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या सीएपीएफ परीक्षा में बैठ सकते हैं। परीक्षा के तीन चरण हैं - लिखित परीक्षा, मेडिकल टेस्ट एवं इंटरव्यू। लिखित परीक्षा में कुल 2 पेपर से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पेपर जनरल नॉलेज व रीजनिंग का होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है। जनरल स्टडीज एवं निबंध से संबंधित दूसरा पेपर सब्जेक्टिव होता है।

विशेष जानकारी के लिए यूपीएससी की वेबसाइट **upsc.gov.in** या रोजगार समाचार पत्र अवश्य देखें।

ब्रेक के बाद करियर में शानदार वापसी

कंपनी में छंटनी, करियर चेंज या निजी कारण से नौकरी से ब्रेक। इनके बाद अकसर करियर में वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाता है। कैसे करें शानदार वापसी? जानें यहां

टिप्स

काम से अस्थायी दूरी कई बार दोबारा काम शुरू करने में परेशानी का सबब बन जाती है। कुछ अध्ययनों के अनुसार ऐसे पेशेवरों को वेतन और पद से समझौता करना पड़ता है। वेतन में तुलनात्मक रूप से 10 फीसदी की कमी देखने को मिलती है। अगर किसी कारणवश करियर में आए ब्रेक, तो कुछ बातों का रखें ध्यानः

सीखना रखें जारी : अंतराल व्यक्तिगत कारणों से हो या पेशेवर, वापसी तभी संभव है, जब इसे सीखने का अवसर समझा जाए। ऑनलाइन कोर्सेस, प्री सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप कर स्किल अपडेट करते रहें और प्रोफेशनिंग या पार्ट-टाइम जॉब से दोबारा शुरुआत करें।

रेज्यूमे में गैप को सकारात्मक रूप में पेश करें, ताकि यह सीखने का समय लगे, न कि खाली बैठने का।

छंटनी हो तो : ऐसे में पहले मौजूदा इंडस्ट्री के अनुरूप अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन करें। नेटवर्किंग मजबूत करें, ताकि पुराने संपर्क नए अवसर दे सकें। इस दौरान करियर क्षेत्र में बदलाव पर भी सोच सकते हैं। अपनी रुचि या पहले वाली जॉब से संबंधित अन्य कौशल सीखकर अपने विकल्प बढ़ाएं।

आत्मविश्वास से भरपूर रहें : लंबे करियर ब्रेक के बाद आत्म-विश्वास में कमी के कारण कई लोग उसी पद या वेतनमान पर वापस लौटने में हिचकिचाते हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि व्यक्ति की काबिलियत करियर ब्रेक पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए अपनी क्षमता के आधार पर ही पद के लिए आवेदन करना चाहिए।

श्वेता राकेश

इंटरव्यू में ईमानदारी बरतें

करियर में हुए बदलावों या बीते अनुभवों से जुड़े सवालों का ईमानदारी से जवाब दें। नए रिक्रूमे को रिज्यूमे में शामिल करें। मौजूदा कंपनी के लिए कोई भी नकारात्मक टिप्पणी करने से बचें। यह जरूर बताएं कि आपका अब तक का कार्य अनुभव नई जिम्मेदारियों के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है।

रोजनामचा

वर्गपहेली : 8092

चाएं से दाएं
1. चर्चा करना; जिक्र छेड़ना; विवाह की बात करना (2,3)
6. लज्जाप्रद; लज्जाजद; शर्मनाक (5)
7. उंगलियों से रगड़ना; मर्दन करना; रौंदना (4)
8. टोकना; पतीला (3)
10. उत्पीड़ित; क्षत; क्षतिग्रस्त; घायल; चोटिल (3)
12. उसके लिए; उसके वास्ते; किसी विशेष काम के लिए (3)
14. प्रारब्ध; भाग्य का लिखा; माथा; मस्तक (3)
16. एक छोर से दूसरे छोर तक; इस किनारे से उस किनारे तक (2,2)
17. अचेत; व्याकुल; शिथिल; क्लांत (5)
19. किसी की इच्छानुसार काम करना; इच्छानुसार काम करना; हैरान होना (2,3)

ऊपर से नीचे
1. बढ़िया धान; ,खुशबूदार चावल की एक किस्म (4)
2. आनंद की धूम मची रहना; रौनक होना; लोगों का एकत्र होना (3,3,3)
3. नाड़ी; डंडल; पोली नली; घोड़ों की टाप (2)
4. कुल की मर्यादा रहना (2,1,3,3)
5. ग्रहण करना; थामना; गिरफ्तार करना (4)
9. पिछला; बीता हुआ; दुर्गति; रूप (2)
11. नीचे का भाग; जूते के नीचे का चमड़ा (2)
13. आत्मविश्वास; मनोबल (4)
15. ऊपर से टपकना; मेह पड़ना; वर्षा होना (4)
18. आलेपित; गीला; तर; लिपा; पुता (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्गपहेली : 8091

सुडोकू : 8074

*आसान

			8	9		3	4	
			4	2		5	3	
5								6
	1		7		9		2	
2				1				3
	3		6		2		4	
3								7
		2	3		8	1		
		1	4		7	5		

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8073

7	4	6	2	9	3	8	5	1
8	3	9	5	4	1	7	6	2
5	2	1	7	8	6	3	4	9
2	5	4	6	7	8	1	9	3
1	6	3	9	2	4	5	7	8
9	7	8	3	1	5	4	2	6
4	8	2	1	5	9	6	3	7
6	1	7	4	3	2	9	8	5
3	9	5	8	6	7	2	1	4

पं. राधवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और उत्-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन परेशान हो सकता है। संतान की सेहत का ध्यान रखें। सार्थी में वृद्धि होगी। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। कारोबार के पति भी सचेत रहें। कठिनाइयां आ सकती हैं।

वृष : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। किसी मित्र का आना हो सकता है। खान-सुख में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें।

मिथुन : आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। कारोबार में वृद्धि होगी। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। लाभ के अवसर भी मिलेंगे।

कर्क : मन में शांति और प्रसन्नता रहेगी। मतभूर आत्मविश्वास रहेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में वृद्धि और स्थान परिवर्तन हो सकता है।

सिंह : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान रहेगा। परिवार की सेहत के प्रति सचेत रहें। पिता का साथ मिलेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। सार्थ बढ़ेंगे।

कन्या : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन भी हो सकते हैं।

तुला : मन परेशान रहेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है। सार्थी में वृद्धि होगी। मानदौड़ बढ़ेगी।

वृश्चिक : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। शैक्षिक कार्यों के प्रति सचेत रहें।

धनु : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। सेहत का ध्यान रखें। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। कारोबार में वृद्धि होगी। मानदौड़ अधिक रहेगी। लाभ होगा।

मकर : मन में मिले-जुले भाव रहेंगे। नौकरी में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र का विस्तार भी हो सकता है।

कुंभ : कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। वौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि हो सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा।

मीन : संतान सुख में वृद्धि होगी। मीठे-खान-पान में रुचि बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। वरुणों और वाहन के रखरखाव पर खर्च बढ़ेगा। मानदौड़ बढ़ेगी। सेहत का ध्यान रखें।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋषभकांत गोस्वामी

18 सितंबर, गुरुवार, शक संवत् : 27,भाद्रपद, सौर शक 1947, पंजाब पंचांग : 03, आश्विन मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम :25, रबि - उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत आश्विन कृष्ण द्वादशी रात्रि 11.25 मिनट तक। पुष्य नक्षत्र प्रातः 06.33 मिनट तक, शिव योग रात्रि 09.37 मिनट तक चन्द्रमा कर्क राशि में (दिन रात)।
सूर्य दक्षिणायन। शरद ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। संन्यासिनां श्राद्ध। द्वादशी का श्राद्ध। गण्डमूल प्रातः 06.33 मिनट से।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

मेरे घर में क्रम से मेरी पत्नी, मां, बेटी और मेरी भी तबीयत बिगड़ती रहती है। कृपया तबीयत में सुधार के कुछ उपाय बताएं। – शुभम वर्मा, प्रयागराज

■ आपकी रसोई ईशान कोण में है, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या का कारण है। रसोई से लगकर शौचालय है, जो दिशा के अनुसार भी गलत है। दोनों की दीवार एक होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रसोई में उत्तर दिशा में एक छोटा फाउंटेन लगाकर नित्य चलाएं, एक पीला स्फटिक का पिरामिड रखें। एक बर्तन में सप्तधान्य भरकर रसोई में रखें। शौचालय में हल्की पीली पट्टी टॉयलेट सीट के चारों ओर लगा दें। नहाने तथा टॉयलेट का एरिया अलग कर दें। बीच में से विभाजित करना भी ठीक रहेगा।

फिर मां पर प्रहार

देश में बढ़ रही सियासी कटुता में एक नए अध्याय का जुड़ना जितना दुखद है, उतना ही शर्मनाक भी। पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी को उचित ही निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां संबंधी एआई-जनरेटेड वीडियो को तमाम सोशल मीडिया मंचों से हटा ले। यह आशंका पहले भी जताई गई थी कि एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमता के जरिये मनचाहे वीडियो गढ़े जा सकते हैं, किसी भी राजनीतिक हस्ती का फर्जी वीडियो बनाया जा सकता है। यह आशंका अब अपने बुरे स्वरूप में साकार हुई है और अदालत को हस्तक्षेप के लिए मजबूर होना पड़ा है। पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने एक याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में बिहार कांग्रेस पार्टी, उसके नेता राहुल गांधी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्स (ट्विटर) इंडिया और मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक को भी नोटिस जारी किए हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि भूल करने वाले सुधार करेंगे और उनके खिलाफ अंतिम या अप्रिय आदेश की नौबत नहीं आएगी। चंद विपक्षी नेताओं ने सियासी लाभ के लिए जो वीडियो बनाया है, उसका बचाव किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकता।

यह समस्या बहुत बड़ी है। हमारे देश की राजनीति ने अभी तक यह फैसला नहीं लिया है कि किस हद तक एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। यह सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या एआई की मदद से राजनीति करना सही है? जहां तक डाटा या उसके विश्लेषण की बात है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर अपने किसी विरोधी को निशाना बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाए, तो यह शुद्ध रूप से तकनीक का दुरुपयोग है। यह एक बहुत बड़ा खतरा है कि आप मशीन या एआई को आदेश देते हैं और अपने विरोधी संबंधी पाकिस्तान ऑडियो-वीडियो सामग्री प्राप्त कर लेते हैं। संक्षेप में अगर कहें, तो प्रस्तुत मामले में जो सामग्री गढ़ी गई है, उसमें प्रधानमंत्री स्वयं में अपनी मां से फटकार सुन रहे हैं। यहां यह दलील पेश की गई है कि मां का अपमान नहीं किया गया है। हालांकि, एक मां का फर्जी वीडियो बनाना और उन्हें अपने बेटे के प्रति नकारात्मक भाव या नाराजगी प्रकट करते हुए दिखाना, एक तरह से अनैतिकता व अपमान ही है। अगर ऐसे वीडियो बनाने की रियायत तमाम लोगों को दे दी जाए, तो किस-किस तरह के वीडियो आएंगे और माहौल किस तरह बिगड़ेगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

अगर फर्जी वीडियो बनाने की रियायत दे दी जाए, तो किस-किस तरह के वीडियो आएंगे और माहौल किस तरह बिगड़ेगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

क्या ऐसे वीडियो बनाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? एआई की मदद से सकारात्मक वीडियो का निर्माण तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आ सकता है, पर नकारात्मक वीडियो बनाना संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। बेशक, एआई सृजन का नया क्षेत्र है, पर पूरी दुनिया में यह आग्रह है कि एआई का सदुपयोग किया जाए। एआई का दुरुपयोग वास्तव में समाज की विफलता है। यह मनोरंजन नहीं है, यह कुत्सित मानसिकता है। इससे केवल कटुता ही बढ़ सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इधर के दिनों में प्रधानमंत्री की मां जी को अनावश्यक रूप से सियासी समर में खींचा जा रहा है। मां एक सम्मानित शब्द-भाव है, उससे खिलवाड़ की राजनीति मानवीयता के अभाव से ग्रस्त है। जरूरी है कि राजनेता संयम का परिचय दें और एआई का दुरुपयोग न करें। ध्यान रहे, आप किसी की ओर एक उंगली उठाते हैं, तो अनायास तीन उंगलियां खुद आपकी ओर होती हैं।

जल बहाव की राह में न बसें बस्तियां

के के पांडेय | प्रोफेसर, अर्बन मैनेजमेंट, आईआईपीए

तमाम मानव बस्तियों में बुनियादी ढांचों का 'ऑडिट' होना ही चाहिए। जो इमारतें गलत बनी हैं या आपदा झेलने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें तत्काल गिरा देना चाहिए।

पहाड़ी इलाकों में जल-प्रलय ने नदियों के साथ ही शहरों के जल-प्रबंधन की ओर हमारा ध्यान फिर से खींचा है। बेशक, इस साल मानसून ने विशेषकर जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ज्यादा तबाही मचाई है, पर यहां जान-माल की क्षति कम हो सकती थी, यदि हमने पूर्व की आपदाओं से सबक सीखा होता।

यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि पहाड़ी राज्यों में नदियों के पाट में कई ढांचे अनियोजित तरीके से खड़े किए गए हैं। ये कैसे तैयार हुए, यह अलग बहस का विषय है, लेकिन इससे नदियों का प्राकृतिक बहाव-क्षेत्र अवरुद्ध जरूर हो गया। दुर्भाग्य से मैदानी इलाकों की भी यही स्थिति है। शहरों का लगातार विस्तार हो रहा है और पानी बहने का नैसर्गिक रास्ता रिहायशी क्षेत्र बनता जा रहा है। नतीजतन, अत्यधिक बारिश के कारण जब पानी अपने तेज वेग में बहता है, तो सब कुछ बहा ले जाता है।

समायोजित योजना, यानी मास्टर प्लान की कमी भी इसकी एक बड़ी वजह है। कई शहरों में समावेशी योजनाओं का अभाव है। अगर कहीं यह बनी भी है, तो उसके क्रियान्वयन में तमाम तरह की चुनौतियां हैं। जल-निकासी प्रणाली का भी कई जगहों पर अभाव है। होना तो यह चाहिए था कि जहां मास्टर प्लान नहीं है, वहां जल-निकासी की कोई ठोस योजना अमल में लाई जाती। मगर ऐसा नहीं किया गया। अलबत्ता, नियमित रख-रखाव व मरम्मत के अभाव में अथवा छोटी-छोटी नालियों भी बारिश में दम तोड़ने लगी हैं।

सीवर और सड़कों की खस्ता हालत ने शहरों की सूरत और बिगाड़ दी है। इनके नियमित देखभाल की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। पहाड़ी राज्यों में भी आमतौर पर सड़कों की मरम्मत तब की जाती है, जब वे चलने के काबिल नहीं रहतीं। नियमित रूप से ध्यान न दिए जाने के कारण ही मैदानी इलाकों में जलभराव की समस्या दिखती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की।

फुटपाथों के अतिक्रमण ने भी मुश्किलें बढ़ाई हैं। सामान्य बाढ़ ही नहीं, बादल फटने के कारण आने वाली 'फ्लैश फ्लड' भी इसीलिए ठहर जाती है, क्योंकि अतिक्रमण से नालियां अवरुद्ध रहती हैं। आलम यह है कि ज्यादातर जगहों पर पैदल चलने वाले लोग इसीलिए बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखते हैं, क्योंकि वहां फुटपाथ या तो हैं नहीं, या फिर अतिक्रमणकारियों के कब्जे में हैं।

स्थानीय निकायों में दक्ष लोगों के अभाव से यह समस्या और भी गहरा जाती है। योजना-निर्माण और क्रियान्वयन, दोनों ही स्तरों पर कुशल हाथों की देश में कमी है। इस कारण नियोजन और रख-रखाव समय पर पूरे नहीं हो पाते। मसलन, सुरक्षा संबंधी ऑडिट बमुश्किल हो पा रहे हैं।

जाहिर है, इन सब मुश्किलों से जूझने के लिए पूंजी की दरकार है, जिसका अभाव बना हुआ है। नगर निकायों के पास बजट की भारी कमी है। माना जाता है कि शहर प्रबंधन के कामों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 10 से 12 प्रतिशत हिस्सा खर्च होना चाहिए, लेकिन अपने देश में यह एक प्रतिशत के आसपास है, यानी जहां 10 रुपये की जरूरत है, वहां सिर्फ एक रुपये का आवंटन हो पा रहा है।

इन चुनौतियों से पार पाने के लिए कुछ काम किए जा सकते हैं। सबसे पहले, हमें ढांचागत व्यवस्था को बेहतर बनाना होगा। सभी शहरों के लिए न सिर्फ मास्टर प्लान बनना चाहिए, बल्कि यह भी ध्यान रखना होगा कि वह व्यावहारिक बने। उसमें बुनियादी ढांचे के रख-रखाव को लेकर भी अलग से आवंटन हो। अभी नगर निकाय जो बजट बनाते हैं, वह एक तयशुदा दरें पर होता है। मसलन, पिछले बजट से दस प्रतिशत अधिक बढ़ाकर नया बजट तैयार कर लिया जाता है। उसमें जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता। लिहाजा, स्थिति का वास्तविक आकलन करते हुए तमाम हितधारकों के सहयोग से बजट तैयार किया जाना चाहिए।

इसी तरह, सुधार के उपायों में जन-भागीदारी, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और निजी क्षेत्र, सभी का सहयोग लेना चाहिए। बेंगलूरु, इंदौर जैसे शहरों में ऐसा हो रहा है, जिस कारण सार्वजनिक कामों के लिए अच्छा-खासा बजट स्थानीय निकायों के पास जमा हो जाता है।

तीसरा, जल-निकासी की बेहतर योजना बनानी होगी। इसमें पानी के नियमित बहाव का आकलन तो होना ही चाहिए, साथ ही, यह भी पता किया जाना चाहिए कि बारिश के समय स्थानीय जल-निकासी प्रणाली पर किस हद तक दबाव बढ़ जाता है। 'स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज' को दुरुस्त करना होगा, जो अभी या तो बने नहीं हैं या उपयुक्त नहीं हैं। यह जल निकासी का एक बड़ा नाला होता है, जिसकी दरकार मैदानी और पहाड़ी, दोनों क्षेत्रों को है। सड़कों को सुगम बनाना और फुटपाथों का ध्यान रखना भी जरूरी है। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत निर्देश भी दिया था, क्योंकि सड़कों की खराब दशा से जलभराव की आशंका बढ़ जाती है।

अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ने इस साल बजट में 'अर्बन चैलेंज फंड' की घोषणा की है। इसमें 10 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसके तहत शहरी विकास की चुनौतियों का समाधान किया जाएगा और शहरी पुनर्विकास को रचनात्मक परियोजनाओं से बढ़ावा दिया जाएगा। ये पैसे देश के 100 शहरों पर बांटे जाएंगे कि नगर निकाय और राज्य सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी और बॉन्ड के माध्यम से तीन गुना पैसे जुटाएंगे। इस तरह, 10 हजार करोड़ रुपये का यह आवंटन 40 हजार करोड़ रुपये का बन सकता है, जो काफी बड़ी रकम है। इसके बेहतर इस्तेमाल के लिए हमें अपने शहरों को तैयार करना होगा।

जाहिर है, हमारे पास अब भी अवसर है। सरकार की योजनाओं और जन-अपेक्षाओं में तालमेल बिठाना होगा। यदि हम कारणों की पड़ताल करके उसे दूर करने का प्रयास करें, तो जल-सैलाब से नुकसान काफी हद तक कम कर सकते हैं। पहाड़ी राज्यों में ही यदि मकान-दुकान या रेस्तरां आदि बनाते समय यह आकलन कर लें कि पानी का प्राकृतिक बहाव उन पर कितना प्रभाव डाल सकेगा, तो काफी राहत मिल सकती है।

इसी संदर्भ में शहरी नवीनीकरण को लेकर भी परियोजनाएं चलाई जानी चाहिए। विशेषकर, विषम इलाकों में बुनियादी ढांचों का 'ऑडिट' होना ही चाहिए, और जो इमारतें आपदा झेलने में सक्षम न हों, उनको तत्काल गिरा देना चाहिए। यह बेशक एक सख्त फैसला होगा, पर यूरोप के देशों में इसके सकारात्मक नतीजे दिखे हैं। हमें पुनर्निर्माण या नवीनीकरण को बढ़ावा देना ही होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

पश्चिमी देशों में प्रवासियों के खिलाफ क्यों बढ़ रहा गुस्सा

हर्ष वी पंत | प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन

ब्रिटेन में बदल रहा राजनीतिक माहौल चिंतनीय है। वहां शनिवार को इंग्लिश डिफेंस लीग ने प्रवासी विरोधी रैली का आयोजन किया, जिसमें डेढ़ लाख के करीब लोग पहुंचे। प्रवासियों के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में लोगों का सड़कों पर उतर आना ब्रिटेन जैसे उदार देश में आश्चर्य की बात है। यह यूरोप में प्रवासियों के खिलाफ फैल रहे असंतोष का संकेत दे रहा है। रैली का आह्वान लीग के नेता टॉमी रॉबिन्सन ने किया था, जिनके खिलाफ काफी आरोप हैं और जो कई बार जेल भी जा चुके हैं।

रैली में प्रवासियों का विरोध करने वाले पूरे पश्चिम जगत के दक्षिणपंथी नेटवर्क का जमावड़ा दिखा। यहां तक कि जाने-माने उद्यमी एलन मस्क ने भी इसे वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। इसमें कई लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्लोगन 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' लिखी टोपी पहनी थी। रैली में यह साफ-साफ पढ़ा जा सकता था कि प्रवासियों के खिलाफ अमेरिका में जो उभार हो रहा है, ब्रिटेन भी उससे प्रेरित है। यहां इंग्लिश डिफेंस लीग मौके का फायदा उठाने की कोशिश में है। यह दल लोगों को तात्कालिक रूप से इकट्ठा करने और भावना भड़काने के लिए हाल में ब्रिटेन में प्रवासी व्यक्ति द्वारा एक बच्ची के साथ शोषण की घटना का इस्तेमाल कर रहा है। अप्रवासी पृष्ठभूमि वाले कट्टरपंथियों द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों ने भी भय और अविश्वास को बढ़ाया है। यानी, वैश्विक परिदृश्य में स्थानीय घटनाओं का तड़का लगाकर प्रवासियों को बाहर निकालने की भावना इन दिनों जोर पकड़ने लगी है।

प्रवासियों के खिलाफ अमेरिका में जो उभार रहा है, ब्रिटेन भी उसी ओर बढ़ चला है। इसके कई कारण हैं, जिनका हल तलाशना चाहिए।

ऐसा क्यों हुआ है? दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से ब्रिटेन समेत पश्चिम के धुर दक्षिणपंथी समूहों में यह भावना घर कर रही है कि प्रवासियों के कारण उनकी सांस्कृतिक अस्मिता खतरे में है और उनकी पहचान पर संकट आ गया है। उन्हें अपने लिए अवसर खत्म होने का डर भी सता रहा है। इस रैली में इन्हीं सबको उभारने की कोशिश की गई। एक तथ्य यह भी है कि अब तक हाशिये पर रही इंग्लिश डिफेंस लीग धीरे-धीरे मुख्यधारा में आ रही है। यह ब्रिटेन और दुनिया के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। हालांकि, वहां यह भी समझना होगा कि पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। वहां रोजगार कम हो रहे हैं। जब ऐसी स्थिति आती है, तो जाहिर तौर पर इसका ठीकरा बाहर वालों पर फोड़ने की कोशिश होती है। बाद में, इसमें भावनात्मक बल देने के लिए संस्कृति और पहचान से जोड़ दिया जाता है। दूसरी ओर, प्रवासियों में भी कई समुदाय हैं, जो वहां के समाज से मेल-जोल नहीं बढ़ा पाते। इस कारण भी आक्रोश बढ़ने लगता है।

ब्रिटेन में चुनावी राजनीति की बात करें, तो वहां एक नई 'रिफॉर्म यूके पार्टी' उभरी है। इसके नेता नाइजल फराज हैं, जो प्रवासी विरोधी हैं। आज ब्रिटेन में चुनाव हो जाएं, तो इसके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आने की प्रबल संभावना है। ब्रिटेन में जो माहौल है और लोगों की भावना स्थापित दलों के खिलाफ होती जा रही है, वह एक नया पहलू है। यह एक हद तक ट्रंप के नक्शे कदम पर चलने जैसा है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह रिपब्लिकन पार्टी की प्रकृति को पूरी तरह बदल दिया, वही काम नाइजल फराज अलग पार्टी बनाकर कर रहे हैं। दोनों जगह पैटर्न एक तरह का ही है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन में यह चलन खास है।

ब्रिटेन की स्थापित पार्टियों-लेबर और कंजरवेटिव ने इनके खिलाफ मोर्चा जरूर लिया है, लेकिन वे प्रवासियों की आमद कम नहीं कर पा रहे, और यही उनकी कमजोरी साबित हो रही है। इसी का फायदा उठाकर राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक चुनौतियों को इकट्ठा कर प्रवासी विरोधी भावना को तूल देने की कोशिश हो रही है। यह भावना अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी से लेकर मध्य यूरोप तक देखी जा सकती है। मतलब साफ है कि ब्रिटेन का राजनीतिक माहौल अंदरूनी तौर पर बदलता जा रहा है। प्रवासी विरोधी रैली में बहुत सारे लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री केर स्टार्मर के खिलाफ भी लगे हैं। वहां लेबर और कंजरवेटिव पार्टी के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी है। जाहिर है, हमें इन घटनाओं पर नजर बनाकर रखनी होगी, क्योंकि प्रवासियों के खिलाफ तेज होता यह विरोध अनिवासी भारतीयों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, जिनकी संख्या तकरीबन 18 लाख है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

धर्म से सब कुछ मिलेगा

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः।

यह महर्षि कणाद का एक महत्वपूर्ण वाक्य है, जिसे सदा ध्यान में रखना चाहिए। इसके अर्थ को समझना बहुत आवश्यक है। यहां धर्म वह है, जो अभ्युदय अर्थात सांसारिक विकास देता है और निःश्रेयस अर्थात मोक्ष भी देता है। अभ्युदय और निःश्रेयस, ये दोनों शब्द हमारे दर्शन में विशेष स्थान रखते हैं। ईश्वर हमें प्रेरित करते हैं कि हम ऐसे कर्म करें, जिससे इस लोक में भी हमें सब कुछ मिले और परलोक में भी सब कुछ मिले। लौकिक फल हमें मिले और अलौकिक फल भी। भगवान ने हमें संसार का सबसे बड़ा फल मनुष्य जीवन निःश्रेयस के लिए ही दिया है।

कौन वे महर्षि कणाद? अनुपम त्याग के प्रतीक थे। फसल काटते हुए खेतों में जो अन्न गिर जाते थे, उसी को चुनना और उन्हीं ही भोजन के संसाधन के रूप में व्यवहार में लेना उनकी प्रवृत्ति थी। कण खाकर वह तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए कणाद कहलाए।

हृदय में उनके वाक्य को बसा लीजिए। जिसे करने से भोग भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा, उसी को धर्म कहते हैं। अनेक लोग समझते हैं कि धर्म करने से केवल परलोक में ही कुछ मिलेगा। समझते हैं कि परलोक में ही ईश्वर के समान परिवेश मिलेगा, पर ध्यान रहे, धर्म करने से इस लोक में भी कल्याण होता है। अभ्युदय अर्थात लौकिक संपत्ति, धन-संपत्ति, बच्चे, पत्नी, सुंदरता, प्रतिष्ठा इत्यादि। हमें अभी यहां मिली हुई सुविधाएं अभ्युदय ही हैं। धर्म केवल यही नहीं देता, मोक्ष भी देता है। कोई संदेह नहीं कि हमारा अंतिम पड़ाव मोक्ष है।

मृत्यु को बेवकूफी में ही कहीं अंत कह दिया जाता है। मनुष्य जीवन में अंतिम पड़ाव तो भगवान का धाम है, लेकिन यह बात हमारे ध्यान में नहीं आती है। लोगों को मोक्ष देने के लिए ही भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। मोक्ष देने के लिए ही भगवान अल्पवस्त्र से व्यक्त हो जाते हैं। यहां सोचना चाहिए कि भगवान आपको मोक्ष कैसे देंगे? इसके लिए आप भक्ति कीजिए। भगवान ने हमें जीवन दिया और कहा कि अब मोक्ष के लिए तत्पर हो जाओ। श्रद्धावान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, पर सावधान रहें, अंधभक्ति को श्रद्धा नहीं कहते हैं।

अकंपित विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। कंपित विश्वास से लाभ नहीं होता है। हमें तत्पर श्रद्धा के लिए प्रेरित करने के लिए ही ईश्वर अवतार लेते हैं। तत्पर का अर्थ है, जुड़ने की बुद्धि।

मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा कि गुरु वाक्य और शास्त्रों के वाक्य में इधर-उधर कुछ भी नहीं है। अकंपित विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। कंपित विश्वास से लाभ नहीं होता है। हमें तत्पर श्रद्धा के लिए प्रेरित करने के लिए ही ईश्वर अवतार लेते हैं। तत्पर का अर्थ है, जुड़ने की बुद्धि। जिनसे बड़ा कोई नहीं है, वह ईश्वर लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं और हमें तत्पर बनाने के लिए ही अपने दिव्य धाम से यहां आते हैं। हमें स्वयंसे जोड़ने के लिए ही यहां आते हैं। अतः इधर-उधर कहीं मत भटकिए।

रामानंदाचार्य स्वामी श्रीरामनरेशाचार्य

कैलाश सत्यार्थी | नोबेल विजेता

अन्याय के सामने चुप रहने से कभी शांति नहीं आ पाएगी। सच्ची शांति साहस मांगती है। इसके लिए करुणा की आवश्यकता होती है। इसके लिए कार्रवाई की आवश्यकता होती है। आइए हम करुणामय बनें। आइए हम मानव बनें।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले | 18 सितंबर, 1950

विद्यार्थी जीवन की मर्यादा

मर्यादाहीन जीवन न व्यक्ति के लिए वांछनीय है न समुदाय के लिए। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में हमको एक निर्धारितता और मर्यादा की भावना दृष्टिगोचर होती है। समुद्र की एक मर्यादा है। उसने अपनी एक सीमा बांध ली है। सामान्यतः वह उससे आगे नहीं बढ़ता, नदियों की जल-राशि को वह अपने गर्भ में समा लेता है और उफनता नहीं। यदि कभी समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़ देता है, तो फिर प्रलय ही मच जाती है। पृथ्वी का ही उदाहरण ले लीजिए। उसकी एक मर्यादा है कि वह स्थिर रहती है। जब वह अपनी मर्यादा को भूल जाती है, तो भूकम्प होता है और सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। व्यक्ति जब अपनी मर्यादा को भंग करने लगता है, तो समाज के लिए खतरा बन जाता है। समाज में परिस्थितियों और अवस्थाओं के भेद के कारण अनेक वर्ग बन गये हैं। व्यक्तियों की भांति इन वर्गों को भी अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए, अन्यथा समाज में अराजकता फैल जायेगी। समाज में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिए मर्यादा-पालन की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता।

विद्यार्थी जीवन की भी एक मर्यादा है। विद्यार्थी का काम ज्ञान और अनुभव करना होना चाहिए। विद्यार्थी-जीवन में जो ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया जाता है, वही मनुष्य को आगे चल कर काम देता है। विद्यार्थी को एक नागरिक की हैसियत से जिन जिम्मेदारियों को उठाना होगा, उसके लिए उसे तैयार होना है। उसे अपने को ऐसी किसी प्रवृत्ति में नहीं उलझने देना चाहिए, जिससे उसके मुख्य लक्ष्य में बाधा पड़े। समाज और राज्य का यह कर्तव्य है कि वे अपने विद्यार्थियों की समुचित शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था करें। विद्यार्थियों पर ही राष्ट्र की भावी महानता निर्भर करती है। विद्यार्थियों में से ही योग्य शासक, चिकित्सक, वैज्ञानिक, शिल्पी और साहित्यकार निकलेंगे। अतः समाज और राष्ट्र को विद्यार्थियों के लिए जीवन के हर क्षेत्र में काम आने लायक योग्यता हासिल करने के लिए सर्वोत्तम साधन और प्रत्येक सुविधा सुलभ करानी चाहिए। विद्यार्थियों में अपने शिक्षकों के प्रति आदर-भाव होना चाहिए। उनमें नया सीखने की तीव्र लगन होनी चाहिए। उनमें अनुशासन होना चाहिए। उनमें चरित्र की दृढ़ता होनी चाहिए। इन गुणों का यदि विद्यार्थी अपने भीतर विकास करेंगे, तो सफल जीवन के अधिकारी होंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं।

साहस और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन

मातृत्व सृष्टि का सबसे सुंदर और सुखद वरदान है। जब कोई स्त्री समाज की तय की हुई मानदंडों को पारकर इसे अपनाती है, तब यह सिर्फ मातृत्व नहीं रह जाता, बल्कि साहस और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन जाता है। लोक गायिका देवी ने 'सिंगल मदर' बनकर वही साहस दिखाया है। विवाह के बंधन में बंधे बिना मातृत्व स्वीकारना न केवल व्यक्तिगत निर्णय है, बल्कि समाज के लिए एक संदेश है कि औरत की पहचान केवल रिश्तों से नहीं, उसकी अपनी इच्छाशक्ति और आत्मसम्मान से तय होती है। इससे पहले नीना गुप्ता ने भी यही साहस दिखाया था। उन्होंने समाज की आलोचनाओं की परवाह न करते हुए बेटी मसाबा गुप्ता को जन्म दिया और आज वही बेटी अपनी पहचान व उपलब्धियों के लिए जानी जाती है। इन दोनों स्त्रियों ने यह साबित किया है कि मां बनने के लिए किसी सामाजिक मुहर की जरूरत नहीं, बल्कि दिल में उठे मातृत्व के स्वर को अपनाने का हौसला चाहिए। उनका यह कदम आने वाली पीढ़ियों की स्त्रियों को प्रेरित करेगा कि वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जिएं।

कुमारी शबनम, टिप्पणीकार

लोक गायिका देवी ने 'सिंगल मदर' बनकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अपने इस फैसले का एलान करते हुए उन्होंने कहा कि वह विवाह में विश्वास नहीं करतीं और मातृत्व का अनुभव करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने आधुनिक चिकित्सा पद्धति का सहारा लिया और बच्चे को जन्म दिया। उनका इस तरह मां बनना समाज के लिए एक मिसाल है, क्योंकि इससे उस पारंपरिक सोच को चुनौती मिलती है, जिसमें बच्चे के जन्म में पिता के योगदान को रेखांकित किया जाता है। देवी ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे की तस्वीर भी साझा की, जिसके बाद उन्हें ढेर सारी बधाइयां मिलने लगीं हैं। उन्होंने इस कदम को लोग भरपूर सराह रहे हैं। इससे सिर्फ यही पता नहीं चलता कि वह कितनी साहसी हैं, बल्कि महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके व्यक्तिगत अधिकारों की वह कितनी बड़ी हिमायती हैं, इसका एहसास भी होता है। आज जब महिलाएं सामाजिक बंधनों को पूरी तरह तोड़ पाने में सफल नहीं हो सकी हैं और शादी उनके जीवन का अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया हो, तब सार्वजनिक दुनिया में रहने वाली इस लोक गायिका ने अकेले मातृत्व सुख पाने का न सिर्फ फैसला किया, बल्कि डंके की चोट पर इसका एलान भी किया। देवी का यह कदम महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह बदल रही सामाजिक परंपरा का संकेत है।

अंकुरी मिश्र, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

एकल मातृत्व

विदेश में एकल मातृत्व ढलान की ओर

नैतिकता-नैतिकता में अंतर होता है। हर जगह समान नैतिकता नहीं है। यूरोप और अमेरिका के दक्षिणपंथी इस बात के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं कि गर्भ में जो बच्चा आ गया, चाहे वह जैसे भी आया, उसे मारा नहीं जा सकता, क्योंकि वह एक जीव है और उसमें प्राण आ चुका है। मगर विवाह से पहले शारीरिक संबंध बनाने को वह बहुत महत्व नहीं देते। विवाह के बिना बच्चे हो जाएं, वह भी उनके लिए बड़ा मुद्दा नहीं होता। उनके लिए बड़ा मुद्दा तो यही है कि जो जीव गर्भ में आ गया, उसे जीने का अधिकार है। उसे कतई गुनकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।

मगर भारत में लोगों के लिए गर्भ में आया बच्चा ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, बल्कि एक समय जो जितना बड़ा दक्षिणपंथी था, उसे तकनीक ने मौका दिया, तो उसने जमकर बच्चों को मारा। केवल अविकसित भ्रूण को नहीं, बल्कि बीस-पच्चीस सप्ताह के गर्भ को भी मार गिराया और आज भी यह सतत जारी है। कई जगह तो स्वीकार्य परंपरा थी बच्चियों को दूध में डुबोकर मारने की। अगर सही से याद हो, तो उसे 'दूधपीटी' कहते थे। मजेदार बात यह है कि जो-जो समुदाय गर्भ में पल रहे भ्रूण को मारने में सबसे आगे थे, वे विवाह से पहले शारीरिक संबंध बनाने के सबसे प्रबल विरोधी रहे, आज भी हैं। अब कौन सही है, कौन गलत, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन व्यक्ति बचपन से जिन चीजों को परिवार से सीखता रहता है, वे उसको अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान लगती हैं। जीवन-मूल्य बन जाते हैं वे। मगर इस आधार पर यह तय करना अनुचित होगा कि भारत का विचार अधिक सही है अथवा यूरोप और अमेरिका का विचार अधिक सही? सबकी अपनी विकास-यात्रा है, सबकी अपनी सोच है। हां, जो भी अति की तरफ जाएगा, वह समाप्त होने को बाध्य है। उसका एक-न-एक दिन अंत जरूर होगा।

यूरोप में गर्भ बचाने के चक्कर में 'सिंगल मदर' की संकल्पना आगे बढ़ी और वह इस कदर व्याप्त हो गई कि अब परिवार के प्रति प्रेम फिर से लौट रहा है। बलात्कार के बाद भी गर्भ ठहर जाने पर बच्चा पैदा ही करना होगा, इस पर विचार-विमर्श चल रहा है। भारत में भी धीरे-धीरे अनगिल परंपराएं ढलान पर हैं। सबकी अपनी-अपनी नैतिकता है, जिसमें अलग-अलग प्राथमिकताएं हैं, पर वास्तव में दिक्कत तब होती है, जब कोई व्यक्ति, समाज और सभ्यता संबंधी आम सोच को किनारे लगाकर अति की तरफ जाने लगता है। हालिया घटनाओं को हमें इसी संदर्भ में देखना चाहिए। वास्तव में, हमारे लिए मध्य मार्ग ही बेहतर है।

भूपेंद्र सिंह, टिप्पणीकार